MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have not given the notice. Today, there is no Question Hour, no Zero Hour. *(Interruptions)*

SHRI D. RAJA: Sir, Friday has one procedure; Saturday has another procedure. *(Interruptions)* It is a very serious matter. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You give notice. We will see...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, I have given the notice. *(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, there are so many other things. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing....*(Interruptions)*....

SHRI D. RAJA: Sir, if you say that it could be taken up on Monday...*(Interruptions)*...I am ready to agree. Sir, it is a very serious matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chairman has to decide. Please give notice. *(Interruptions)* No. You give the notice, then only it will be considered. Otherwise, without notice, how can I...*(Interruptions)*...Now, the hon. Minister.

GOVERNMENT BILLS

The Appropriation (No. 4) Bill, 2007; and

The Appropriation (No. 5) Bill, 2007

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:

> That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2007-2008, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also beg to move:

> That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2006, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, as far as the Supplementary Demands are concerned, we ask for authorization of gross additional expenditure of Rs. 33,290.87 crores of which the cash outgo is only Rs. 11,869.60 crore. Technical supplementaries are for Rs. 21,420.82 crore and a token provision for new services, new instruments of services of Rs. 0.45 crore is also asked. Of the total cash outgo of Rs. 11,869.60 crores, an amount of Rs. 9,900 crores, that is 83 per cent of the cash outgo, is on three major items. First meeting additional expenditure on interest liabilities and the market stabilization scheme will cost us Rs. 4,500 crores. Transfer of States and Union Territory Governments for meeting additional Central assistance for projects besides grant on loan for externally aided projects will be Rs. 4,500 crores; and export related subsidies, Rs. 900 crores. Sir, other items include subvention to cooperative banks to NABARD, post metric scholarship scheme, equity capital in Delhi Metro Rail Corporation Ltd., re-imbursement of losses incurred by NAFED and the price support operations for mustard and grants-in-aid to State plans for agriculture. The cash outgoes likely to be offset by savings and other grants and the higher revenue receipts. Therefore, the deficit

targets indicated in the Budget Estimates will be adhered to. The details are in the papers and I request the hon. House to discuss the Appropriation Bills and return the Bills to Lok Sabha.

The questions were proposed.

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): उपसभापति महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पर आपने बिल पर आपने जो मुझे बोलने के लिए इजाजत दी, उसके लिए आपका आभार। वित्त मंत्री महोदय ने एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 4 और 5 सदन के पटल पर विचार के लिए रखा है। आमतौर पर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है कि जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स होती हैं, उसके लिए वित्त मंत्री सदन में अपना प्रस्ताव लेकर आएं। चूंकि लोक सभा में यह एप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका है, राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है, स्वाभाविक है कि यह यहां भी पास होगा, क्योंकि वित्त विधेयकों पर आमतौर पर सबकी स्वीकृति के रूप में यह काम होता है।

उपसभापति महोदय, मैं अनुभव कर सकता हूं कि वित्त मंत्री बहुत प्रसन्न मुद्रा में होंगे, क्योंकि, शायद मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसलिए उनको कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी वह मेरी बात को हमेशा ध्यान से सुनते हैं।

श्री पी॰ चिदम्बरम: नहीं। आप बोलिए।

श्री रामदास अग्रवाल: प्रसन्नता इसलिए होगी, क्योंकि देश की इकोनोमी दुनिया की इकोनोमी के साथ-साथ बहुत ऊंचाई पर चल रही है। हमारी जीडीपी 9.1 परसेंट आ रहा है। इस देश में विदेशों से खूब पैसा आ रहा है, पानी की तरह विदेशी धन इस देश में आ रहा है। हमारे यहां पहले कहा जाता था कि इस देश में दूध और घी की नदियां बहती हैं, कोई जमाना था।

श्री उपसभापति: अब पैसों की नदियां बहती हैं।

श्री रामदास अग्रवाल: वह दूध और घी तो गायब हो गया, मगर अब हमारे देश में हर गली-कूचे में विदेशों से आया पैसा बह रहा है। यह देश के आने वाले भविष्य के लिए कितना लाभदायक होगा, मैं अभी नहीं कह सकता, यह तो समय बताएगा और अगर लाभदायक हुआ तो निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री का नाम इतिहास में बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): इनका नाम इतिहास में ऐसे ही लिखा जाएगा।

श्री रामदास अग्रवाल: अब यह तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर देश की तरक्की होती है, देश यदि आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है और अगर देश में जो चाहिए वह व्यवस्था बनती है, तो कोई वित्त मंत्री किसी भी पार्टी का हो वह स्वागत योग्य होगा। सवाल यह आ जाता है कि जब हम अखबार में यह देखते हैं कि हमारे देश में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलूर में कितने करोड़पति, मल्टी-मिलिनियर्स, बिलिनियर्स हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। ...(**व्यवधान**)... आपका भी नाम है उसमें। लेकिन यह स्वाभाविक बात हमारे मन में है कि देश के अंदर कोई एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार दुनिया में सबसे अधिक wealthy हों, बहुत अच्छा है, इसमें हमें क्या आपत्ति है। हमारे देश की धरती के पुत्र हैं और अगर उनकी सम्पदा बढ़ती है, तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन, उपसभापति महोदय, अभी परसों ही, अभी सुश्री रिबैलो जी और श्रीमती वृंदा कारत जी आई नहीं हैं, उन्होंने वित्त मंत्री के साथ उलझते हुए यह कहा कि देश की सम्पदा, देश की आर्थिक नीति के कारण, कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। यह प्रश्न विचारणीय है। क्योंकि, अगर केवल मैं, बी॰जे॰पी॰ का आदमी, कहूं तो शायद कांग्रेस के लोग यह कहेंगे कि आपका तो सोचने का तरीका ही दूसरा है, विपक्ष का है और हम अपना विपक्ष का धर्म निभाते भी है। लेकिन जब कांग्रेस के लोग यह कहें, तो यह विचारणीय है। कल जब लोक सभा में यह बिल डिस्कस हो रहा था, उस समय भी और यहां के सभी माननीय सांसदों ने भी समय-समय पर इस बात की चिंता प्रकट की कि क्या इस देश की सम्पदा पर, इस देश की सम्पदा के दोहन पर कुछ ही परिवार के लोगों का हक होगा या 100 करोड़ जो दूसरे लोग हैं, जो गरीब हैं, BPL में हैं, उनको भी इन सम्पदाओं में कहीं न कहीं तरक्की होने के कारण लाभ मिलेगा। यह बात भी कहीं न कहीं सोचने की है। उनकी भागीदारी कहां हो, कैसी हो, उन्हें देश की तरक्की का लाभ कैसे मिले, देश के आर्थिक ढांचे में उनकी भागीदारी कैसे बने, यह सवाल इस देश के सामने है। वित्त मंत्री जी जिस पार्टी के द्वारा नॉमिनेटिड हैं, उस पार्टी ने भी हमेशा यही कहा है — इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर आज सोनिया गांधी जी के समय तक यही कहा है कि हम गरीब के साथ हैं, हमारा हाथ

उनके साथ है। उपसभापति महोदय, यदि हम यह मान लें कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है, हम यह मान लें कि हम सब तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इस सदन में हमारे साम्यवादी लोग, कांग्रेस के लोग, हम लोग समाजवादी लोग बार-बार यह क्यों कहते हैं कि इस देश में गरीबी बढ़ रही है, इस देश में आम आदमी परेशान है, इस देश में आम आदमी को आर्थिक ढांचे का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। उपसभापति महोदय, यह सवाल हमारे सामने एक यक्ष के रूप में खड़ा है और इसका जवाब जब कांग्रेस के लोग देते हैं तो केवल अपनी आर्थिक नीतियों का गुणगान करते हैं, लेकिन वास्तव में समाधान कैसे होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। उपसभापति महोदय, मैं आज सारी आर्थिक नीतियों के ढांचे पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तीन-चार विषय ऐसे हैं, जिन पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपसभापति महोदय, हम सबको जब यह प्रसन्नता होती है कि देश की तरक्की हो रही है, उस समय मैं सदन में बैठे हुए माननीय सांसदों से, जिनकी जिम्मेदारी है इस देश के बाकी लोगों के लिए, प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा उस आदमी का विचार करिए, जो गांव के कोने में पड़ा है, सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर है, क्या हम उसकी तरफ देखेंगे या हम किसी दो लाख करोड़ रुपए के मालिक की तरफ देखेंगे और अपने आप में बहुत आनन्द का अनुभव करने लगेंगे। उपसभापति महोदय, देश के अंदर डिस्पेरिटी, असमानता पैदा होती जा रही है। यह असामान्य व्यवहार, असामान्य धन का एकत्रीकरण, यह देश के सामूहिक उत्थान के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, जिसके कारण देश में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। अभी पिछले दिनों ही यहां पर भी चर्चा की गई कि कश्मीर में टैरेरिस्ट्स क्यों पैदा होते हैं? श्री अब्दुल्ला साहब कहते थे, इसलिए क्योंकि वहां लोग बेकार हैं, वहां जवानों के पास काम नहीं है। नक्सलवादी क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। उत्तर-पूर्व में लोग जो आतंकवादी बनते हैं या वहां रोज बम-ब्लास्ट करते हैं, हत्याकांड करते हैं, अपहरण करते हैं या अनेक प्रकार के अनाचार, दुराचार करते हैं, तो इसके पीछे हमारे राजनीतिक नेता सब यही बात कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। देश का नौजवान भटकने के साथ-साथ देश को दूसरे रास्ते पर ले जा रहा है, जहां पर आतंक की सृष्टि हो रही है, terrorism की सृष्टि हो रही है और उसके कारण सारे देश में अशांति हो रही है। यदि इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा, तो हम कब इसके ऊपर निर्णय करेंगे और कैसे हम उन नौजवानों को इस प्रकार के गलत रास्तों पर जाने से रोकेंगे? क्या यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है, क्या यह disparity का परिणाम नहीं है, क्या यह उन चीजों का परिणाम नहीं है कि हज़ारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन यहां दूसरी स्थिति है। यहां मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जो बताया गया, वह मैं उद्धृत करना चाहता हूं। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से पूछा था — "Whether the Government has so far made any assessment as to how much money is being lost by way of various concessions, subsidies and relaxations being given by the Government to industry, farmers, SEZs, PPZs, etc." माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है— "Yes Sir. The estimated overall revenue forgone on account of various concessions given by the Government amounts to Rs. 1,58,661 crores."

मुझे नहीं मालूम कि हमारे CPM के लोग इस बात को कैसे digest कर पा रहे हैं। क्या इस देश की सब्सिडी की व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है? किसानों से सब्सिडी वापस लेने की बात होती है, fertilizer से सब्सिडी कम करने की बात होती है, oils के दाम बढ़ाने की बात होती है, लेकिन वर्ष 2004-05 के लिए 1,58,000 करोड़ रुपए का estimate बताया गया है, जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडी 23,653 करोड़ रुपए दी गई। मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं कि SEZs को या इंडस्ट्रीज को या इन लोगों को सहायता क्यों दी जाती है, लेकिन मैं comparison करना चाहता हूं कि इनकी सहायता करने के कारण, बाकी जिन sectors के लोगों की सहायता आपको करनी है, उनके लिए आपके पास धन नहीं है। किसानों को ज्यादा पैसा देने के लिए आपके पास धन नहीं है, आपके पास सीमित साधन हैं। स्वाभाविक है कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन पैसा इन सब्सिडीज़ में जा रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में जा रहा है, फिर वह पैसा केवल कुछ ही हाथों में जा रहा है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 1,58,000 करोड़ रुपए का estimate केवल एक साल का है, आगे कितना होगा, यह वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बताएं। आपने इसमें 2004-05 का estimate दिया है, 2006-07 का estimate क्या है और 2007-08 का estimate क्या है, कितने हजार करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में इस देश में दिया जा रहा है, यह मंत्री जी हमें बताएं इसके ऊपर हमारे सामने सवाल यह है कि हम किसानों को क्या दें, हम बेरोज़गारों के रोज़गार के लिए क्या व्यवस्था करें, शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था करें, गरीब आदमी को मदद पहुंचाने के लिए कैसी व्यवस्था करें। Comparison करने के लिए मैं आपके सामने यह सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमें इन सवालों के जवाब आने वाले समय में देने पड़ेंगे।

उपसभापति जी, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि disparities हैं, कुछ लोग कमा रहे हैं और कुछ लोग गंवा रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी के संदर्भ में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, मुझे याद है कुछ दिन पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं अपने किसी वक्तव्य में यह स्वीकार किया था कि आम उपभोक्ता की चीजों के दाम 25 परसेंट से ज्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने जो 25 परसेंट दाम बढ़ने की बात कही है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं आपके सामने यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि अगर 25 परसेंट बढ़ोत्तरी आप कहते हैं, तो यह average होगा, मैं average की बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आम व्यक्ति के लिए जो मूलभूत आवश्यक वस्तुएं हैं — चाहे गेहूं है, चाहे चावल है, चाहे आटा है, चाहे दाल है, चाहे साग-सब्जियां हैं, चाहे घी है, चाहे तेल है, चाहे जो भी चीजें हैं —इन चीजों के दाम 25 परसेंट नहीं बढ़े हैं, अगर आप अलग से calculate करेंगे, तो इन चीजों के दाम 50 से 70 परसेंट तक बढ़ चुके हैं। उपसभापति महोदय, अगर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें 50 से 70 परसेंट बढ़ जाती है तो फिर व्यक्ति अपना जीवन कैसे यापन करेगा, कैसे वह इस बढ़ते हुए आर्थिक प्रगति के सुख का अनुभव कर सकेगा? उसके पेट में तो वही चूहे दौड़ते रहेंगे, उसको वहीं सुई चुभती रहेंगी कि उसे खाने को नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो मंहगा मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसी हालत में, एक तरफ अगर हम तरक्की का दावा करें और दूसरी तरफ जिनके पेट को भरने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उनके दामों पर नियंत्रण न कर सकें, तो ऐसी आर्थिक रचना का लाभ किसको मिलेगा? आर्थिक रचना का यह लाभ फिर आम आदमी के पास नहीं जा रहा है। आज वह आम आदमी अपने आपको ऐसा अनुभव कर रहा है कि जैसे इस देश में उसकी कीमतों के बढ़ने के मामले में चिंता सब जताते हैं, समाधान कोई नहीं करता। चिंता तो हम सब करते हैं क्योंकि हम उस चिंता से चिंता व्यक्त करने तक सीमित हैं, हमने उस कष्ट को शायद अनुभव नहीं किया, लेकिन उपसभापति महोदय, यह आज की सच्चाई है कि दामों में बढ़ोतरी जरूरत से ज्यादा हो गई है।

उपसभापति महोदय, मैं दामों में बढ़ोत्तरी के बारे में पहले बोल चुका हूं, लेकिन मैं एक और तीसरा विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हमारे विचार के लिए कंसर्न हैं, वह यह है कि पिछले दिनों इस देश में, बंगाल में जो कुछ हुआ, उपसभापति महोदय, उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर दूसरी एक लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है, इसलिए सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और वह रिटेल ट्रेडिंग को दूसरे बड़े लोगों के हाथ में सौंपने का काम है। उपसभापति महोदय, मैं अपनी तरफ से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में दोनों कान खोल कर सुनें, दोनों कान खोलकर इसलिए सुनें क्योंकि देश के अंदर छोटा-मोटा व्यापारी आज उद्वेलित है, परेशान है, क्योंकि उसको यह भय और शंका हो गई है कि सारे लोग, ये बड़े-बड़े लोग, सारे आकर के उनके रिटेल ट्रेड को अपने हाथ में कब्जा कर लेंगे।

उपसभापति, महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हजारों वर्षों से रिटेल ट्रेडिंग के काम में साधारण से साधारण व्यक्ति involve होता है, वह अपनी रोजी-रोटी सेल्फ रूप में कमाता है, स्वमेव अपना रोजगार पैदा करके यह अपना रोटी पैदा करता है, लेकिन अगर रिटेल ट्रेडिंग के अंदर इस प्रकार के बड़े-बड़े लोगों का आगमन हो गया, उपसभापति महोदय, मैं उन बड़े-बड़े लोगों से भी कहना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं, बड़े लोगों से यह कहना चाहता हूं कि महाराज, आप लोग कृपा करके सब्जी और दूध-दही बेचने का काम मत करो ...(व्यवधान)... मत करो, यह काम तुम्हारा नहीं है, तुम पेट्रोलियम इंडस्ट्री लगाओ, तुम पावर हाउस लगाओ, तुम infrastructure लगाओ, यह क्या, दूध-दही बेचने का काम करने लग गए ...(व्यवधान)... वह जो चलाए, चलाए, लेकिन कम से कम साग-सब्जी बेचने का काम, यह काम कोई उनका है? मुझे शर्म आती है, जब मैं कभी सुनता हूं कि हमारे रिलाइन्स के अंबानी साहब आकर बाजार में दुकान खोलेंगे। उपसभापति महोदय, यह तमाशा है, इस देश के अंदर बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है ...(व्यवधान)... । अरे भाई, रहने दो, यह छोटा काम है, छोटे लोगों के लिए रहने दो, गरीबों का काम, है गरीबों के लिए रहने दो, तुम्हारे लिए सारी दुनिया के बाजार खुले हैं, तुम वहां काम करो, उसमें जाओ, हमारे इन गरीब लोगों को जो हजारों साल से देश की सप्लाई लाइन को मेन्टेन किए हुए हैं, उनके ऊपर आघात मत करो और मैं सरकार समेत इन सारे लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर इस पर ज्यादा *दिखाई गई या ज्यादा दबाव डाला गया तो इस देश के अंदर और कई प्रकार के तुफान खड़े हो जाएंगे, लेकिन व्यापारी इस देश में इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इस व्यवस्था को खंडन करना गलत है, इस व्यवस्था को सुरक्षित रखना आवश्यक है और इस व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। उपसभापति महोदय, इस व्यवस्था को तोड़ने से इस देश के अंदर आंतरिक द्वंद्व छिड़ जाएगा, इस देश के अंदर आंतरिक कलह मच जाएगी, रोजगारी टूट जाएगी और लोग बेकार होकर सड़कों पर आएंगे और ऐसे काम करेंगे, जो अभी हमारे और नौजवान कर रहे हैं।

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभापति महोदय, इसलिए मैं साफ-साफ सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में ध्यान रखे इसमें दखलंदाजी करने का प्रयास न करें और साथ ही बड़े उद्योगपतियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए दुनिया के बाजार खुले हैं, वे वहां जाएं और काम करें और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें और जो ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखण्ड): डायमंड प्लैटिनम के बारे में भी ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: उस पर मैं आ रहा हूं... मैं उस पर भी आऊंगा। उपसभापति महोदय, यह सवाल मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित कर रहा हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): अहलुवालिया साहब के कहने से बात मत कीजिए, अपनी बात कहिए। ...(**व्यवधान**)... आप अपनी बात कहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): बजाज साहब, इनकी बात को सुन रहे हैं न आप?

श्री राहुल बजाज (महाराष्ट्र): मैं सब ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: उन्होंने कान में अभी ईयरफोन लगा रखा है, इसलिए सुनते नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... लेकिन बजाज साहब तो अभी स्कूटर बेचते हैं, साग-सब्जी नहीं बेचेंगे। मुझे नहीं मालूम, अगर उन्होंने कुछ सोचा हो तो।

उपसभापति महोदय, अभी अहलुवालिया साहब ने कहा, मुझे उन्होंने एक प्वाइंट याद दिला दिया, वैसे मैं बोलने वाला था। वे concerned हैं forward trading के लिए। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले अगर मार्केट अप एंड डाउन होती थी, बाज़ार में किसी भी चीज़ के भाव डिमांड-सप्लाई के प्रिंसिपल पर अप या डाउन होते थे कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है? उस आधार पर हुआ करता था, लेकिन आज डिमांड-सप्लाई तो खत्म हो गई और शेयर मार्केट में परफॉरमेंस खत्म हो गई। हमारे अमर सिंह जी की कंपनी चले या न चले, अमर सिंह जी का नाम चलता है शेयर बाज़ार में। अगर इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, मुझे माफ कीजिएगा अमर सिंह जी, मैंने आपका नाम तो वैसे ही लिया ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): चलने दीजिए, हर जगह चलता है।

श्री रामदास अग्रवाल: नाम चलता है। अगर मैं बड़ा उद्योगपति हूं और मैंने खरीदना शुरू कर दिया, तो सारे खरीदना शुरू कर देते हैं और मैंने बेचना शुरू कर दिया, तो सब बेचना शुरू कर देते हैं। महोदय, यह परफॉरमेंस नहीं है, आधार परफॉरमेंस नहीं है। यह आधार सप्लाई और डिमांड नहीं है। आधार बन गया है सट्टेबाज़ी। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह : कहीं रेड न पड़वा दें चिदम्बरम जी, आपके कहने से!

श्री रामदास अग्रवाल: मेरे यहां भी हो चुकी है, आप चिंता न करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अग्रवाल जी, आप बोलिए।

श्री रामदास अग्रवाल: यह तो सरकार का काम है, करती रहती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: हां, यह बात ठीक है।

श्री रामदास अग्रवाल: हममें से बहुत लोगों के यहां ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

श्री रामदास अग्रवाल: अपनी-अपनी शिकायतें हो सकती हैं और उन शिकायतों के प्रति मेरी सहानुभूति हो सकती है। महोदय, मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं, forward trading के लिए, मुझे मालूम था कि मुझे इस विषय पर यहां बोलना है, मेरी पार्टी ने मुझे कह दिया था, इसलिए चार दिन से मैं शेयर मार्केट पर नज़र रख रहा था, कमोडिटी मार्केट पर नज़र रख रहा था, सोने-चांदी की मार्केट पर नज़र रख रहा था, ऑयल मार्केट पर नज़र रख रहा था। महोदय, ऑयल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उत्पादन कम नहीं हुआ। ओपेक कंट्रीज़ ने कहीं यह घोषणा नहीं की है कि ऑयल का प्रोडक्शन

हम घटा रहे हैं, किया है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे जानकारी नहीं है और अभी तक तो उनकी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह 50 डॉलर से बढ़कर 98 डॉलर तक चला गया। ! पेट्रोल का प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम 50 डॉलर से बढ़कर 98 डॉलर चला गया और उससे भी पहले जाएं, तो 18-20 डॉलर से 98 डॉलर हो गया। यह सारी दुनिया का पैसा, उपसभापति महोदय, यह चिंता का सवाल है, सारे विचारशील देशों के लिए, सारे डेवलपिंग और अंडर-डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि क्या दुनिया का सारा पैसा इसी प्रकार से कुछ देशों के हाथों में चला जाएगा? महोदय, हम इस बात को जानते हैं कि जब धन गलत हाथों में चला जाता है या किसी एक हाथ में सिमट जाता है, तो उसका दुरुपयोग होता है, दुनिया में शांति भंग होने के आसार बन जाते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: कुछ देश और कुछ उद्योगपति!

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, पेट्रोलियम के लिए जैसा मैंने आपसे कहा, मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान में सोने-चांदी की डिमांड ज्यादातर दीवाली पर आती हे। दीवाली के दिनों में ज्यादातर सोना-चांदी महंगा होता है, क्योंकि डिमांउ ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। महोदय, पिछले एक हफ्ते में चांदी दो हज़ार रुपया किलो बढ़ गई और कल रात से लेकर अभी तक, दो हज़ार रुपया कम हो गई। अब दो दिन में, चौबीस घंटे में, चांदी का उत्पादन घटा या चांदी की डिमांड बढ़ी, या क्या हुआ? सवाल इस बात का नहीं है महोदय, लोग सट्टा करते हैं, वे करें, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता?, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं यह विषय कि अगर मैं मार्किट में ब्याह-शादी के लिए कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता हूं तो मुझे व्यापारी कहता है कि चांदी का भाव 20,000 रुपए है। जब मैं उसे कहता हूं कि मैंने तो आज अखबार में पढ़ा था कि 19,000 रुपए है, तब वह कहता है कि आप 24 घंटे पहले की बात करते हैं। आप बहुत पुराने आदमी हो गये हैं, अब तो यह 20,000 हो गया है। महोदय, कुछ ही घंटों में एक-एक हजार रुपए किलो या 200 से 300 रुपए तक दस ग्राम सोने का भाव बढ़ जाए तो इस देश की आर्थिक तरक्की का कौन सा आधार है जो इसको सपोर्ट करता है?

श्रीमती जया बच्चन: आजकल तो खाना भी एक मिनट में बन जाता है।

श्री रामदास अग्रवाल: इसका अनुभव मुझे नहीं है। खाने का अनुभव तो मुझे है लेकिन बनाने का अनुभव मुझे नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी पत्नी खाना बनाती है इसलिए मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : डायवर्शन मत कीजिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): सर, यह कैसे पता लगेगा?

श्री उपसभापति: पता लग जाएगा। उन्होंने कह दिया है, पता लग जाएगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, आज बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल: सर, यह बड़ा गंभीर विषय है लेकिन आप सबने इसको बड़ा रोचक बना दिया है वरना आर्थिक विषयों पर नींद आने लगती है। महोदय, मैं जो विषय आपके सामने रख रहा हूं, यह आम आदमी से संबंध रखता है। आज गांव का आदमी भी शादी ब्याह के लिए चांदी खरीदता है। आज शहर का रहने वाला - चाहे मीडियम क्लास का हो, चाहे लोअर मीडियम क्लास का हो— वह भी दो-चार तोला सोना-चांदी ब्याह-शादी या अन्य कामों के लिए अपने परिवार के लिए खरीदता है। महोदय, आज उसको लूटा जा रहा है और इसलिए लूटा जा रहा है क्योंकि कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह व्यक्ति उस दिन का भाव सेटल कर सके। कौन उस भाव को सेटल करेगा? Who will settle the rate in the retail market? अगर रिटेल मार्किट में यह सेटल नहीं होगा तो उपभोक्ता लूटा जाएगा। आज उसको लूटा जा रहा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने फॉरवर्ड ट्रेडिंग चालू कर दी—आपने अच्छा किया, आप जाने—हमने शुरू किया था, हम जाने। लेकिन सवाल यह है कि उपभोक्ता का प्रोटेक्शन कौन करेगा? प्रोटेक्शन तो उस सरकार को करना पड़ेगा जो आज सत्ता में बैठी है। वह यह कहकर अलग नहीं हो सकती कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग आपने चालू की थी इसलिए आप जिम्मेदार हैं। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आज यह सरकार जिम्मेदार है जो स्वयं इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती जहां पर उपभोक्ता का प्रोटेक्शन हो सके।

महोदय, शेयर मार्किट की बात करना चाहता हूं। मेरे पास आज अगर किसी कम्पनी के सौ शेयर्स हैं तो मुझे मालूम नहीं होता कि उस कम्पनी का क्या हाल है। मैंने शेयर्स ले लिए हैं। दूसरे दिन मैं देखता हूं कि उसके भाव दस गुणा बढ़ गए हैं,

मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन चौथे ही दिन मैं देखता हूं कि उसके भाव चार गुणा गिर गए हैं। इस प्रकार मैं कभी लखपति होता हूं और कभी खाकपति हो जाता हूं। यह सब क्या है?

श्री अमर सिंह: यह सेंसेक्स है जो घटता और बढ़ता है।

श्री रामदास अग्रवाल: यह कौन-सा सेंस है, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन इसमें सेक्स जरूर है।

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): मंत्री जी बताएंगे कि क्या है?

† [**شری شاہد صدیقی :** منتری جی بتائیں گے کہ کیا ہے؟]

श्री रामदास अग्रवाल: वित्त मंत्री जी को आप इस परिस्थिति में मत डालिए, वह ठीक नहीं है। मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि There is uncertainty in the market. The exploitation by the traders has to be stopped. That has to be controlled, and some mechanism should be developed in the country so that the forward trading businessmen should not exploit the consumer. This is my request to the hon. Finance Minister. Sir, I think the hon. Finance Minister will respond to it. महोदय, अब मैं टैक्सेशन के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्रीमती जया बच्चन: आप प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे। उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार क्या नीति ला रही है?

श्री रामदास अग्रवाल: मकैनिज्म का मैंने बोला है।

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): आपकी बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बाज़ार पर तो नियंत्रण नहीं है लेकिन किसान के उत्पाद का दाम वे तय करते हैं। वह गलत है।

श्री रामदास अग्रवाल: वह तो मैंने पहले ही सदन में निवेदन किया ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: किसान को छूट नहीं है, चीनी मालिकों को छूट दी जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप अमर सिंह जी और उदय प्रताप सिंह जी को मत देखिए।

श्री रामदास अग्रवाल: उपसभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को जरूर प्रसन्नता है कि टैक्स रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। यह बहुत अच्छा है कि इस देश के खजाने में पैसा आता है तो हम सब को भी खुशी होगी। उसी कारण वित्त मंत्री शायद हमारे भी एलाउंस के बारे में विचार करेंगे और अगर पैसा नहीं आएगा तो कहां से करेंगे। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने यह जो सर्विस टैक्स लगाया है, मुझे नहीं मालूम कि इनको यह बात कहां से सूझी, लेकिन सूझी। मैं समझता हूं कि यह कुछ हद तक बहुत ठीक है। लेकिन कोई भी टैक्स हनुमान जी की पूंछ जैसा नहीं हो सकता कि वह बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आप टैक्स के लगाने की सीमा और उसका स्पष्टीकरण कि कौन देवाल है और कौन लेवाल है, किस पर लगना है, किस पर नहीं लगना है, यह आप डिसाइड करिए। लेकिन उसको एकदम खुला वाइड स्कोप छोड़ दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि जो टेक्सेशन आथॉरिटीज़ हैं वे मनमाना व्यवहार कर रही हैं। मैं इस बात के लिए अगर वित्त मंत्री जी चाहेंगे तो कई उदाहरण उनके सामने पेश कर सकता हूं। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती जया बच्चन: महोदय ...**(व्यवधान)**

श्री उपसभापति: नहीं अभी नहीं। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती जया बच्चन: He is yielding, Sir ...**(व्यवधान)**

श्री अमर सिंह: He is yielding, Sir ...**(व्यवधान)** वे यील्ड कर रहे हैं, सर।

---

†[]Transliteration in Urdu Script.

श्रीमती जया बच्चन: इन्होंने इतना इंपोर्टेंट मुद्दा उठाया है कि सर्विस टैक्स के नाम पर शादी-विवाह में लोगों से यहां तक इस तरह से इतने हद तक सवाल किया जाता है कि आपने ब्यूटी पॉर्लर में कितना खर्च किया।

श्री उपसभापति: यह सर्विस टैक्स नहीं है।

श्रीमती जया बच्चन: This is true and I have got it. I can bring it and lay it on the Table.

श्री अमर सिंह: सर, इनके पुत्र अभिषेक बच्चन की शादी में इनको नोटिस मिली है कि ब्यूटी पॉर्लर में कितना खर्च हुआ ...**(व्यवधान)**

श्री उपसभापति: जब आपका टर्न आएगा तो आप इस पर बोलिए, मगर उनको बोलने दीजिए। अग्रवाल जी, आप बोलिए। अगर इसी में आपकी पार्टी का समय खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे।

श्री रामदास अग्रवाल: उपसभापति महोदय, मैं अपने पोइंट पर बात कर रहा हूं, मैं गैर पोइंट पर बात नहीं कर रहा हूं।

श्री उपसभापति: मैंने कब कहा कि आप पोइंट पर बात नहीं कर रहे हैं। मगर आप यील्ड मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**

श्री शाहिद सिद्दीकी: सर, महिलाओं के सामने तो यील्ड करना चाहिए, नहीं करेंगे तो बहुत गलत होगा।

† [**شری شاہد صدیقی :** سر، مہیلاؤں کے سامنے تو ییلڈ کرنا چاہئے، نہیں کریں گے تو بہت غلط ہوگا۔]

श्री उपसभापति: तो आप नहीं करते न।

श्री रामदास अग्रवाल: उपसभापति महोदय, यह जो सर्विस टैक्स लगाया गया है, जैसा मैंने कहा कि मैं अभी किसी टैक्स का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन जो टैक्स लग चुका है उसके गुण और अवगुण व्यवस्था के बारे में चिंतन करने के लिए सदन के सामने प्रश्न रख रहा हूं। मेरा टैक्स से विरोध का सवाल अभी नहीं, वह जब आएगा तब देखूंगा, अभी नहीं है। अभी मेरा सवाल यह है कि आपने सर्विस टैक्स की व्यवस्था की। उपसभापति महोदय, उस सर्विस टैक्स के अन्तर्गत एक्सटॉर्शन होता है, एक्सप्लॉएटेशन होता है और लूट मची हुई है। यह टैक्स का नेट किसको मालूम है, पता नहीं। टैक्सिंग आथॉरिटीज ने इंसपेक्टर बना दिए हैं, जो हर व्यापारी के घर पर, दुकान पर जाकर उनको ह्रास करना शुरू कर दिया है।

श्री अमर सिंह: वे घूस मांगते हैं।

श्री रामदास अग्रवाल: वह तो है। लेकिन यह जो एक्सटॉर्शन शुरू हो गया है और उसके कारण पनपने वाला भ्रष्टाचार यह सर्विस टैक्स के नेट को बर्बाद करके छोड़ देगा, सरकार की आमदनी बढ़ने के बजाए बाद में जो लोग इसके इंचार्ज बने हैं या जो लोग इंसपेक्टर बने हैं, उनकी आमदनी ज्यादा हो जाएगी और सरकार की कम हो जाएगी। उपसभापति महोदय, यह सवाल इसलिए आता है कि आपने इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया कि कौन से, कौन से सर्विस के काम इसके अंदर टैक्स नेट में आएंगे। उपसभापति महोदय, बहुत विवाद है, सैकड़ों जगह, हजारों जगह इसको लेकर आपत्तियां खड़ी की गई हैं, कहीं पर क्लेरिटी नहीं है। जिस प्रकार से सर्विस टैक्स में क्लेरिटी नहीं है, रिकवरी किससे की जाएगी और कौन लेगा, कौन देगा, कौन जमा कराएगा, कौन काटकर लेगा इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से streamline करने की आवश्यकता है। उपसभापति महोदय, वरना इस सर्विस टैक्स के अंदर भ्रष्टाचार बहुत अधिक पनप जायेगा और उसके कारण हम लोग फिर से एक भ्रष्टाचारी तंत्र की ओर बढ़ जायेंगे, जो सारे देश को, सारे व्यापार को और सारे लोगों को परेशान करने वाला होगा।

उपसभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सर्विस टैक्स के मामले में कोई निश्चित व्यवस्था को आयाम दें, ताकि वहां पर पनपने वाला भ्रष्टाचार और वहां पर पनपने वाला दबाव, ये दोनों वहां समाप्त हो सकें।

---

†[]Transliteration in Urdu Script.

उपसभापति महोदय, मैं दूसरी बात टैक्स रिकवरीज़ के मामले में कहना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि देश के खजाने में टैक्स की चोरी नहीं हो, कोई टैक्स चोरी करने वाला बचे नहीं। मैं एक बात सर्विस टैक्स के संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं। आजकल जैसे सेल्स टैक्स में होता है, आपमें से बहुत से लोग जानते होंगे, अगर छह महीने का टैक्स देना है, तो सेल्स टैक्स आफिसर हमारे घर पर आयेगा और कहेगा कि अगले छह महीने में से तीन महीने का टैक्स जमा करा दो। अगर आपके ऊपर दस लाख की लायबिलिटी है, तो वह आपसे कहता है कि आप पन्द्रह लाख दे दो, पांच लाख हम बाद में भर देंगे, इस प्रकार की प्रेक्टिस शुरू हो गयी है। अगर आपका धन-संग्रह बढ़ा है, इसमें कोई इस प्रकार की प्रेक्टिस प्रारम्भ न हो जाए इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको इन अफसरों को यह कहना पड़ेगा कि जो टैक्स बनता है, उतना ही टैक्स लिया जाए, एडवांस में टैक्स वसूली न की जाए।

उपसभापति महोदय, इन सारी बातों को मैंने आपके सामने रखा है और मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि देश के अंदर इस समय जो व्यवस्था बढ़ी है, जो इकोनोमिक बूम आया है, उस बूम में हम सब सहभागी बनना चाहते हैं, हम सारे लोग मिलकर इस देश की तरक्की देखना चाहते हैं, आर्थिक ढांचे को ठीक करना चाहते हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं और अपने नौजवानों को हम काम देना चाहते हैं, किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए, हम एसईजेड और एसपीजेड वगैरह को जो सबसिडी देते हैं, जिस उदारता से देते हैं, वही उदारता का भाव किसान के लिए भी एडॉप्ट किया जाना चाहिए। किसान को भी उसी प्रकार से सबसिडी देने के लिए उस समय विचार करना चाहिए, जैसे आप इंडस्ट्रीज को लाखों-करोड़ रुपया देते हैं, उस समय विचार करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: जैसे चीनी मिलों को दे रहे हैं, वैसे ही किसानों को दीजिए।

श्री रामदास अग्रवाल: उसी तरह से किसान के लिए भी, जो इस देश को अन्नदाता है, जिसने अन्न पैदा करके इस देश के सौ करोड़ लोगों को खाना देना है और जो कम से कम भाव पर अपना अनाज बेचने को मजबूर होता है, उसकी सहायता करने के लिए आपकी तिजोरी के ताले खुले रहने चाहिए, न कि केवल एसईजेड और एसपीजेड या बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होना चाहिए। किसानों के लिए भी आपको अपनी तिजोरी के ताले खोलने चाहिए, उनको भी बचाना चाहिए और नौजवों को रोजगार देने के लिए कदम उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं जो कुछ आपके सामने बोला हूं, आपने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सबको मजबूर किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak. Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Grants presented by the hon. Finance Minister. Sir, while supporting, I would like to give some suggestions for the consideration of our hon. Finance Minister. Sir, the achievements of our UPA Government are outstanding. So far as the direct tax collections are concerned, it has recorded a growth of over 43.9 per cent from 1st April to 15th November, 2007. The net tax collections stood at Rs. 1,40,373 crores. I am happy to note that the Income-Tax Department has already issued over 30 lakh refunds in the first seven months of this fiscal involving a total amount of Rs. 18448 crores as on 2nd November, 2007. India's export increased by 19 per cent. All these are indicators for the higher economic growth. Sir, as has been stated, the GDP is nearly 10 per cent but in the agricultural sector we are not getting the desired results. As you know, Sir, 70 per cent of our population lives in the rural areas. We can upgrade the rural sector, particularly the agricultural sector by introducing certain measures. For example, agricultural products are all perishable but, we do not have the required infrastructure to preserve these perishable items. So, we need to have cold storage facilities in all the districts and villages which we do not have now. Sir, nearly, 30 per cent of the total products we get from the growers are destroyed everyday. It is only because of lack of infrastructure, like preservation facilities. We should have our own refrigerated containers. Regarding the agricultural products that we are producing, time has come that we need to have value-added products from fruits and vegetables. We can have a plenty of value-added products from them. There is every possibility of export of these items if we can extend

some help and cooperation to these manufacturing units, so that they can do very well and grab the global market.

Sir, under the Indira Awas Yojna, the unit cost of a dwelling unit has gone up due to increase in the price of raw material like cement, steel, etc. Therefore, I request the Government to increase the Budget accordingly.

Sir, the NREG Programme should be implemented throughout the country. I request the list of works under the NREG Programme be increased. I also request that the duration should be extended. Uner the NREG Scheme, if any donor wants to give financial assistance for creating permanent infrastructure like school buildings, Anganwadi buildings, roads, drains, etc., it should be welcomed. I support such kind of a thing.

We are spending a lot of money on health under the National Rural Health Mission. We should also create permanent infrastructure like PHC, Sub-Centres, so that in case of emergency the villagers have accessibility to such centres.

The rural sector gets facilities through rural banks. But the actual position of the rural banks is not up to the mark. The rural banks are not getting any facilities if you compare them with the nationalised banks. While they are making all the demands, nothing has so far been done. So, I would request the hon. Minister of Finance that the problems being faced by Grameena Banks for years together be looked into and solved.

It is a matter of serious concern that, as per the reports, farmers are committing suicides at regular intervals in most parts of the country, particularly my State, Karnataka and Andhra Pradesh due to indebtedness, loss of crops, due to severe floods and drought.

Sir, our GDP growth is good. The achievements of our service sector and engineering sectors are remarkably good. I would like to congratulate the hon. Finance Minister for this.

With these few words, I would like to thank you once again for giving me a opportunity to speak on the Appropriation Bill. Thank you.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, जो ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, पूरक अनुदान मांगे पेश की गई हैं। ये इस सदन में दूसरी बार पेश की गई हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार चलाने वाले और खास तौर पर वित्त मंत्रालय के लोग जो बजट तैयार करते हैं, आखिर उनके नजरिए में, उनके काम करने के तरीके में क्या फर्क है और क्या दोष है? जो आने वाला खर्च है, या जो आने वाली मदें हैं, उनके बारे में उनकी कोई दृष्टि नहीं रहती है। जिस बजट को संतुलित और ठीक तरीके से बनाया जाना चाहिए, वे लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसी नाते सरकार को बार-बार इस प्रकार की मांगों को लेकर सदन के समक्ष आना पड़ता है। मैं अभी इनका कागज पढ़ रहा था। वित्त मंत्री जी ने कहा कि कुछ अपरिहार्य खर्च हो गये, कुछ नए खर्च आ गए, जिसके कारण मुझे कंसोलिडेटिड फंड से यह पैसा खर्च करने की अनुमति लेनी पड़ रही है। वे अपरिहार्य कारण कौन से हैं? उन अपरिहार्य कारणों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री जी ने बताया कि एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि एक्सपोर्ट सैक्टर में संकट आ गया और संकट आने के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 11 प्रतिशत बढ़ गया। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी, इतना ही नहीं, उनको जो दो परसेंट इंट्रेस्ट क्रेडिट पर छूट दिया, उसमें भी सरकार ने उन्हें निर्यात घाटे को सब्सेडाइज किया है, उन्हें सब्सिडी दी है, तथा और भी तमाम प्रकार की रियायतें और सहूलियतें दी हैं। एक तो यह कारण बताया और दूसरा कारण यह बताया कि पेट्रोल और डीज़ल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम बढ़ गए, उसके लिए सरकार को बॉण्ड जारी करना पड़ा। बॉण्ड के अलावा ये जो तेल कंपनियां हैं, इन तेल कंपनियों को भी पांच हजार या पचपन सौ करोड़ रुपए के करीब जो छूट दी गई, यह एक बहुत बड़ी मद तेल के बारे में है। तीसरी बात यह है कि राज्य सरकारों के जो खर्च बढ़ गए, उसके कारण जो तमाम योजनाएं थीं, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए भी हमें पैसे की व्यवस्था करनी पड़ी। मैं एक्सपोर्ट के बारे

में जरूर बताना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा जो खर्च है, अगर उसका विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि हमारे देश का जो अमीर वर्ग है, उसी को राहत देने में यह खर्च किया गया है। अगर आप हमारे कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योगों के बारे में सोचें तो यहां उसके हिसाब से बहुत कम खर्च किया गया है। रामदास जी ने ठीक ही कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो संचालन हो रहा है उसके जो नतीजे हमें दिखाई पड़ रहे हैं , उससे साफ़ झलकता है कि सरकार यहां के जो नागरिक हैं, किसान हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनके मुकाबले देशी और विदेशी पूंजीपतियों के प्रति ज्यादा नरम रुख अख्तियार करती है। मुझे याद है कि इसी सदन में माननीय अमर सिंह जी ने एक स्टेराइट कंपनी के बारे में सवाल उठाया था। इसका करोड़ों रुपया बकाया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया कि चूंकि यह मामला माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है, इसलिए इस पर विचार नहीं हो सकता है। इस प्रकार स्टेराइड कंपनी के करोड़ों रुपए के बकाये का न्यायालय का बहाना देकर छूट दी जा रही है। हमारी पार्टी की सदस्या, नेता जया बच्चन जी ने बताया कि इनके बेटे की शादी में सर्विस टेक्स का जो नोटिस मिला है, वह माली, पंडित, बाल काटने वाले और ब्यूटी पार्लर के बारे में था। मुझे अभी खबर मिली कि जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, इन्होंने चीनी मिल मालिकों को ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है। ब्याज मुक्त इसलिए क्योंकि उन्हें घाटा है। इन्हें चीनी मालिकों के घाटे की बहुत चिंता है, परंतु गन्ना किसानों के घाटे की बिल्कुल चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 3,000 करोड़ रुपया बकाया है और उसके बारे में केन्द्र की सरकार भी चुप है और प्रदेश की सरकार को तो उसकी चिंता ही नहीं है. क्योंकि वह तो मग्न है अपने पार्कों में, मग्न है अपनी मूर्तियों में, मग्न है अपने जलसे में मग्न है सोने का मुकुट पहनने में। पानी की तरह वह पैसा इन्हीं समारोहों और मूर्तियों पर खर्च किया जा रहा है। वहाँ के किसानों के सामने जो संकट है, उसकी कोई चिन्ता उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं है। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ मैं यह भी आरोप लगाना चाहता हूं कि बहुत सी योजनाओं को जो पैसा केन्द्र सरकार से जाता है, उन योजनाओं का पैसा भी ठीक तरीके से प्रदेशों की-सरकारें खर्च कर रही हैं या नहीं कर रही हैं या उस पैसे को दूसरे मदों में divert कर रही हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए, इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए, इसका भी परीक्षण होना चाहिए। हम जो पैसा देते हैं, जो सदन से पास होकर जाता है अगर उस पैसे को अनुत्पादक मदों में या समारोहों या बेकार में मदों में खर्च किया जाए, तो यह बहुत ही बड़ा पाप भी है और अपराध भी है। इसलिए इसको रोकने का इन्तजाम भी होना चाहिए।

मान्यवर, यहाँ पेट्रोल और डीज़ल की बात कही गई। इसमें वित्त मंत्री जी पूँजीपतियों की बात नहीं करते। वे किरोसीन ऑयल या किसान डीज़ल की बात करते हैं। किसान कितना डीजल इस्तेमाल करता है? परन्तु आज जो मोटर की कम्पनियाँ हैं, वे डीज़ल की बड़ी-बड़ी कीमती गाड़ियाँ बना रही हैं। आज बड़े लोग डीज़ल पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आज देश के अन्दर बिजली की बेहद कमी है, बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं की जाती। इसलिए जेनरेटर से बिजली खर्च होती है। जेनरेटर कौन चलाता है? क्या गरीब आदमी चलाता है, किसान चलाता है? आप इसमें भी बड़े आदमियों को ज्यादा राहत देते हैं, ज्यादा छूट देते हैं बमुकाबले गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को, जिसकी आमदनी बँधी हुई है और आप नाम लेते हैं किसान का। एक्सपोर्ट के बारे में, पेट्रोल और डीज़ल के बारे में और राज्य सरकारों को आप जो पैसा दे रहे हैं, उनके बारे में आपकी जो नीति है, वह नीति ठीक नहीं है। वह नीति देश के गरीब लोगों के विरुद्ध जाती है।

मान्यवर, अब रहा सवाल कृषि के बारे में, जो इसमें दिया गया है कि कृषि के क्षेत्र में आप जो पैसा दे रहे हैं, एक तो आप कृषि बीमा कम्पनी के अंतर्गत दे रहे हैं, प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए, फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत और फिर कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत। मान्यवर, मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि आज कृषि की जो स्थिति है, उसके बारे में यह केवल मेरी चिन्ता नहीं है, देश के जितने बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, सलाहकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, सबने इसकी चिन्ता की है और सरकार ने भी कृषि की हालत पर अपनी चिन्ता जताई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो एप्रोच पेपर है, उस एप्रोच पेपर में यह कहा गया है कि खेती की जो 4 प्रतिशत विकास दर है, उसको पाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दरम्यान कृषि की जो विकास दर थी, वह विकास दर, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य से आधे से भी कम है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आप लक्ष्य प्राप्त नही कर पाए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आप स्वयं मानते हैं कि यह बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि जब तक खेती की विकास दर 4 प्रतिशत के करीब नहीं आती है, न तो कृषि लाभकर होगी, न कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा और न ही ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई विकास होगा क्योंकि जब कारण गिनाए जाते हैं, उन कारणों में सबसे बड़ा कारण यही कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र में जो सार्वजनिक पूंजी निवेश है, वह घटता जा रहा है, उसकी उत्पादन क्षमता घटती जा रही है, जो खेती है, उसका कृषि क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है, दामों का संतुलन खत्म होता जा रहा है।

आदरणीय स्वामीनाथन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात को कहा है कि जब तक किसानों को कम से कम अपनी लागत का 50 प्रतिशत फायदा नहीं मिलता है, तब तक वह किसान खेती नहीं करेगा। आप जानते हैं कि आज 60% के लगभग जो किसान हैं, वे मजबूरी में खेती करते हैं। आज कोई किसान खेती करना नहीं चाहता है, विशेषकर नई पीढ़ी के जो लोग हैं, वह खेत के किनारे जाना तक नहीं चाहते, क्योंकि अगर उस किसान परिवार का कोई व्यक्ति बैंक में चपड़ासी है, तो वह ज्यादा बेहतर है। किसान के मुकाबले उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है। जहां पर खेती की स्थिति यह हो, वहां पर आप जितना पैसा दे रहे हैं, वे केवल ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसका केवल नाम होगा या हल्ला होगा कि कृषि पर सब्सिडी दी गई, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी गई, मगर उस सब्सिडी का फायदा कौन उठाता है? इस सब्सिडी का फायदा किसान को नहीं मिलता। इसका फायदा बड़े लोगों को मिलता है या कारखानेदार को मिलता है, हालांकि नाम किसान का ही होता है।

दूसरी तरफ स्थिति यह है कि एक तो कृषि का उत्पादन घटेगा, दूसरी ओर हमारी आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई आबादी को हम पूरी तरह से भोजन नहीं दे पाएंगे। आंकड़े आए हैं कि आज कृषि में अनाज की जितनी उपलब्धता है, उस उपलब्धता में निरंतर गिरावट आ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि विश्व बैंक और आईएमए के निर्देश पर हम जो योजनाएं बनाते हैं और उसी के अनुसार वित्त मंत्रालय का संचालन करते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि जो गरीब हैं, वे गरीब होते जा रहे हैं, जो किसान हैं, वे भूमिहीन होते जा रहे हैं। जब खेती करने में फायदा ही नहीं होगा तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी ही नहीं, नौकरी उसे मिलेगी नहीं, आर्थिक क्षमता उसकी सुदृढ़ होगी नहीं, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि उसे अनाज खरीद कर खाने में भी दिक्कत होगी। आज जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, वह भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। कई प्रश्नों के उत्तर में भी यह बात कही गई है कि पीडीएस सिस्टम में, सस्ती दरों पर जो अनाज आता है, वह गरीबों में बंटने के बजाए मार्किट में चला जाता है। मार्किट में क्यों चला जाता है? इस पर एक स्टडी हुई है और उसके अनुसार यह बात कही गई है 23% के करीब जो राशन की दुकाने हैं, उनमें उनको पूंजी का केवल 12% मुनाफा ही मिलता है, ऊपर से कदम-कदम पर उसमें कितना भ्रष्टाचार भी है। इसलिए बहुत से जो दुकानदार हैं, वे या तो गल्ला उठाते ही नहीं हैं। अगर वे गल्ला उठाएंगे, उसे बेचेंगे तो उन्हें पूरी तरह से मुनाफा नहीं मिलेगा और उसका नतीजा यह होगा कि अफसरों और छोटे दुकानदारों के सामने एक ही विकल्प बचेगा कि वह गेहूं को खुले बाजार में भेज दें। अनाज खुले बाजार में चला गया, उसकी आमदनी बढ़ी नहीं लेकिन अनाज के दाम बढ़ गए...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे.कुरियन): तिवारी जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री बृजभूषण तिवारी: तो उसका नतीजा यही होगा कि अनाज की जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वह निरंतर घटती जाएगी। अगर हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जांचे या परखें तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर आधी से ज्यादा जनरेशन में पौष्टिक आहारों की कमी हो जाए, तो जो लोग 40-50 साल की उम्र पार कर गए हैं, वे तो मौत की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी के जो लोग हैं या आने वाले समय में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर वे भी कुपोषण के शिकार होंगे तो आने वाले समय में हम कैसी पीढ़ी पैदा करेंगे? उनके द्वारा किस प्रकार के भारत का निर्माण करेंगे? इस बात की कल्पना करके ही हम सिंहर जाते हैं ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे. कुरियन): प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

श्री बृजभूषण तिवारी: शायद वित्त मंत्री जी में यह संवेदनशीलता या सैंसिटीविटी न हो। वित्त परिस्थितियों में जो बाँएंसी और बाहरी चमक है, उसी से वह इतने अभिभूत हैं। वह समझते हैं कि सरकार ने जो योजनाएं चला दीं, सरकार ने जो पैसे आवंटित कर दिए, उसी के बल पर देश चमकेगा और जो गरीब आदमी कीड़े-मकोड़े से भी बदतर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, उसके प्रति न उनके मन में दया है और न सहानुभूति है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, विरोध तो करता, लेकिन जैसा कहा गया है कि लोक सभा में यह पारित हो गया है, इसलिए मैं अपनी राय व्यक्त करते हुए समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमर सिंह: सर, एक सेकंड। सर, माननीय सदस्य बृजभूषण तिवारी जी ने अपने सारगर्भित वक्तव्य में बोलते हुए मेरे नाम से उल्लेख किया है कि स्टैरलाइट कंपनी के एक मामले में, वेदांत कंपनी के मामले में मैंने कई बार सदन में प्रश्न उठाया है कि इनके ऊपर करोड़ों रुपए बकाया हैं। वित्त मंत्री जी ने बार-बार यह मामला उठाए जाने पर सदन को यह आश्वासन दिया है कि यह मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। सर, यह मामला न्यायालय में कब तक लंबित रहेगा। मैं वित्त मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं और जानता हूं कि वह बड़े ईमानदार, बहुत योग्य और

बहुत अच्छे वित्त मंत्री हैं, लेकिन वित्त मंत्री बनने से पहले वह इस कंपनी में डाइरेक्टर रह चुके हैं, इसलिए यह उन के हित में है कि वह इस बकाया रकम को वसूल करें ...(व्यवधान)... वह रेड करें, जेल भेजें और कुछ भी करें। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No; no; Okay. ...(*Interruptions*)... That's okay. Shri Mohammed Amin.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बात के लिए आप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

सरकार को जब भी पैसे की जरूरत होगी, वह सदन में आएगी, यह एक रिवाज है, लेकिन इस मौके पर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि यू.पी.ए. की गवर्नमेंट साढ़े 3 वर्षों से काम कर रही है और इस सरकार को वामपंथी पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं, लेकिन उस समर्थन की एक शर्त है और वह है ''कॉमन मिनिमम प्रोग्राम।'' कॉमन मिनमम प्रोग्राम सहमति के साथ, एत्तफाक राय के साथ तय पाया था, लेकिन इन साढ़े 3 वर्षों का रिव्यू किया जाए तो यही बात निकलेगी कि उस प्रोग्राम का बहुत ही कम हिस्सा implement हुआ है, जो अहम हिस्से हैं, वे नजरंदाज किए जा रहे हैं। सर, मैं इस संबंध में जो बात कहना चाहता हूं, यह यह है कि ''अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।'' सर, यह बड़े दुख की बात है। हिंदुस्तान में मजदूर और किसान-ये दो तबके ऐसे हैं जिनकी हालत अगर बेहतर हुई तो मुल्क तरक्की करेगा और अगर इनका दुख बढ़ गया, इनकी मुसीबतें बढ़ गईं तो देश नीचे गिरेगा। तो आज क्या हो रहा है? अलग-अलग तमाम बातों पर विचार करने के बाद जो नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, वह यह है कि आम लोगों की हालत खराब हुई है। हिंदुस्तान में ऐसा एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो यह बोले की साढ़े 3 वर्षों में आजादी के बाद से आज तक, चीजों की कीमत घटी है? वह कभी भी नहीं घटी है, वह मसलसल बढ़ती चली जा रही है और आज तो यह इस मुकाम तक पहुंच गई है कि मुल्क की आधी आबादी दो वक्त पेटभर खाना नहीं खाती। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त भी खाना नहीं मिलता है, इसलिए कि पैसा नहीं है। किसानों की खुदकुशी की बात सारे लोगों को मालूम है और खुदकुशी करने वालों की तादाद वर्ष में लाखों तक पहुंच जाती है। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है? हम कैसे सिर उठाकर चलेंगे? हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हिंदुस्तान कौन से रास्ते पर चल रहा है जहां लाखों किसान अपनी जान दे देते हैं। कहीं-कहीं अखबारों में ऐसी रिपोर्ट भी निकलती है कि पूरे परिवार ने एक साथ जहर खाकर आंख बंद कर ली। क्या सरकार कभी उस पर ध्यान देती है या पता लगाती है कि उसके पीछे वजह क्या है? वह एक ही है कि किसानों को उन की फसल की कीमत नहीं मिलती है। उनका कर्ज बढ़ता जाता है और जब वे कर्ज में डूब जाते हैं, जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अपनी जान देकर, अपमानित होकर, दुनिया से रुखसत होते हैं। यह तो हालत है। अभी कल ही यहां बात हो रही थी कि हिंदुस्तान में कहते हैं कि गेहूं की पैदावार बढ़ी है, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वह प्रोक्युरमैंट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम है। सरकार किसानों को जो कीमत देती है, उसकी डबल कीमत पर वह बाहर से गेहूं मंगवाती है। यह क्या नीति है, क्या पॉलिसी है? यह पॉलिसी किसी की समझ में नहीं आती। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है।

जमाने के अंदर बदले गए, नए राग हैं साज बदले गए।

सब कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रही तो सरकार की पॉलिसी।

महोदय, पॉलिसी वहीं एक ही है, चाहे आप जितनी तकरीरें करते रहें। मंत्री लोग यहां बैठकर सुनते हैं और सुनकर फिर जवाब में गोल-मोल बातें करके चले जाते हैं। वे समझते हैं कि पास तो हो ही जाएगा।

श्री शाहिद सिद्दिकी: जमीं जुम्बद, आसमां जुम्बद, न जुम्बद गुल मोहम्मद। ...(व्यवधान)

†شری **شاہد صدیقی** : زمیں جنبد، آسماں جنبد، نہ جنبد گل محمد۔مداخلت۔

श्री मोहम्मद अमीन: लेकिन डेढ़ साल के बाद, जब सरकार की मियाद पूरी हो जाएगी, जनता के सामने आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। यह जनता, जो इतने दिनों में ठोकर खा-खा कर कुछ सीख रही है, कुछ सीख गई है, वह किसी को नहीं बख्शेगी, मगर सरकार ने अपनी पुरानी पॉलिसियों से कुछ सबक लिया है, या सबक लेने की कुछ कोशिश की है, ऐसा मालूम नहीं होता। उसका नतीजा भुगतना होगा।

†[]Transliteration in Urdu Script.

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कौन नहीं जानता कि इस मुल्क में काले धन का पहाड़ खड़ा हुआ है। इस काले धन के मालिक कौन लोग हैं? उनकी आइडेंटिटि क्या है? उनके पास कैसे काला धन जमा हुआ? वे लोग इन्कम टैक्स न देकर और गैर-कानूनी धंधा करके यह पैसा जमा करते हैं। जिन लोगों के जिम्मे यह काम है कि वे उनको पकड़ें वे लोग भी उनसे मिले हुए हैं और इसलिए उन पर किसी का कोई वश नहीं चलता। सब लोग जानते हैं कि काला धन पेरालल इकोनोमी का काम कर रही है और जिस देश में यह हालत होगी, वह देश कभी तरक्की नहीं करेगा, चाहे आप जितना सिर फोड़ लें। यहां के कुछ नेता आजकल चीन जा रहे हैं, यह बड़ी अच्छी बात है, मगर चीन से वह क्या देख कर आते हैं, उससे उनको कुछ इंसपरेशन मिलता है या नहीं, मालूम नहीं। चीन की जो तरक्की हुई है, उससे तो आज वह अमरीका से टक्कर लेने जा रहा है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब सारा मरकज चीन बनता जा रहा है और उसकी जो इकोनोकिम ग्रोथ है, जो लोग कम्युनिस्टों के मुखालिफ हैं, वे भी मानते हैं कि चीन तरक्की कर रहा है। क्या वजह है कि चीन तरक्की कर गया, जबकि वह हमारे बाद आजाद हुआ। हम पहले आजाद हुए, लेकिन हमारी तरक्की रुक गई, हम मुसीबत में हैं, फंसे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... यह मेरा दूसरा सवाल है।

महोदय, यहां क्या हो रहा है कि सरकार बड़े जोरों से एसईजेड बढ़ाती चली जा रही है, लेकिन एसईजेड में मजदूरों को न तो मिनिमम वेज मिलता है, न उनके काम के घंटों की कोई हद है और न ही रिटायरमेंट के बाद सोशल सिक्युरिटी का कोई इंतजाम है। इधर कौन देखेगा? एसईजेड इलाके में कोई यूनियन बनाने नहीं देते, यूनियन का कोई लीडर उस इलाके में जा नहीं सकता है, उसको परमिशन नहीं है। ऐसे एसईजेड का क्या फायदा, जहां मजदूरों का शोषण और बढ़ जाए? हिंदुस्तान में जो लेबर लॉज बने हुए हैं, उन पर अमल-दरामद नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। उनकी कमाई का हिस्सा प्रोविडेंट फंड में काटकर जमा कर लिया जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के मौके पर उनको वह पैसा मिलता नहीं है, ग्रेच्युटी मिलती नहीं है। जब तक इंसान काम करने के लायक रहता है, काम करता है, लेकिन जब हाथ-पांव कमजोर हो जाते हैं, आंखों से देख नहीं सकता, दांत टूट जाते हैं, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो रिटायरमेंट का टाइम आता है और उस वक्त उसे अगर खाली हाथ घर जाना पड़े तो सिवा भीख मांगने के वह क्या करेगा? यह हमारे लिए अपमान की बात नहीं है। इसको कौन देखेगा? मजदूरों की हालत अगर आप देखें, तो एक चेहरा निकलता है, किसानों की हालत देखें तो एक और चेहरा निकलता है, पूरे देश में महंगाई की मार से देखें तो लोग कराह रहे हैं। इनसे उनको बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कोई तकदीर बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कहां जाएं, किस तरफ जाएं वे लोग।

श्री उदय प्रताप सिंह: अमीन साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक शेर सुना दूं। समता के घर में जाने कैसे वृद्ध हुई संख्या निकली राजाओं और नवाबों की

संसद में चर्चा चलती रही बहारों की,
सूख गई सड़कों पर पौध गुलाबों की।

श्री मोहम्मद अमीन: अभी यहां पर एक सदस्य ने retail estatesके कारोबार के बारे में कहा। चार करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जिस तेजी से FDI इसमें घुस रहा है, उससे वे सारे लोग बेकार हो जाएंगे। कौन इनका सामना करेगा कहां जाएंगे?

Unorganised Sector के मजदूरों का, यह बात सरकार को मालूम है, proportion 93 फीसदी हो गया है, यानी 100 मजदूरों में से 93 unorganised sector में है, जिनके लिए आज तक हिन्दुस्तान में कोई कानून नहीं बना और देश की तरक्की के दावे किए जा रहे हैं। इन मजदूरों ने 8 अगस्त को पूरे हिन्दुस्तान में स्ट्राइक की, जिसमें 4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और सर, आपके जरिए मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि Budget Session के मौके पर लाखों मजदूर पार्लियामेंट के सामने मज़ाहिरा करने के लिए आएंगें, देश के लोगों को यह बताने के लिए कि इस सरकार ने Unorganised Sector की तरफ, हमारी तरफ आज तक देखा नहीं, हमारे लिए कोई कानून आज तक बना नहीं।

सरकार दावा करती है कि inflation घट रहा है, inflation यानी इफराते जर। अगर inflation का रेट कम हो तो महंगाई क्या बढ़ती है? सियासत में जोर-जबर्दस्ती नहीं चलती, argument चलता हैं आपकी बात से लोग कन्वींस होंगे तो वे आपका साथ देंगे, अगर आपकी बात से कन्वींस नहीं होंगे तो जोर-जबर्दस्ती से यह काम चलने वाला नहीं है।

हर कोई यह कह रहा है कि जो अमीर थे, वे और ज्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे, वे और ज्यादा गरीब हो गए। हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ था तो करोड़पति लोगों की तादाद कितनी थी और आज वह तादाद कहां तक चली गई है? बिड़ला कम्पनी के पास 500 करोड़ रुपया था, अभी लाखों करोड़ रुपयों की मालिक बिड़ला कम्पनी हो गई है।

श्री मंगनी लाल मंडल: बिड़ला तो पीछे चला गया, अब अम्बानी का जमाना है।

श्री मोहम्मद अमीन: अब नए लोग आए हैं- बिड़ला टाटा, अम्बानी, वाल चन्द हीरा चन्द, सूरज चन्द, लाडर मल, मफत लाल, कन्नौडिया, वन्नौडिया, कितने नाम गिनवाएं आपको। यही लोग इस मुल्क को मुट्ठी में ले चुके हैं और सरकार तमाशा देख रही है। इनके पास इतनी ताकत हो गई है कि सरकार इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: अमीन साहब, ये सारे आपने कोलकाता के नाम पढ़े, मुम्बई के नाम पढ़ते तो बॉटलीवाला, बनातवाला ...

श्री अमर सिंह: अनिल अग्रवाल।

श्री मंगनी लाल मंडल: दारुवाला।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: हां, इन सबका नाम आता।

श्री मौहम्मद अमीन: हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं इन लोगों के बारे में। आपकी जान-पहचान ज्यादा है।

सर, इस वक्त गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं और यह तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से शहरों में भीड़-भाड़ बढ़ गई है। रोटी की तलाश में इंसान मारा-मारा फिरता है। एक जमाने में लोग कोलकाता और मुम्बई जाते थे। कोलकाता में तो अभी तक लोग जा रहे हैं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र से, सब जगह से कोलकाता में लोग जा रहे हैं और जो गरीब वहां आते है, हम लोग उनको अपने गले लगा लेते हैं, कभी उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुल्क एक है, मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जाने का हक सबको है। लेकिन, सवाल यह है कि अगर गांव में उनको रोजी मिल जाए तो वे उस जगह को छोड़कर, जहां उन्होंने जन्म लिया है, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। सिवाय पश्चिमी बंगाल और केरल के पूरे हिन्दुस्तान में सब जगह land reform बराएनाम हुआ है, land reform की बात भी कोई नहीं करता और जब तक basic land reform नहीं होगी, जमीन किसानों को नहीं मिलेगी, आप लाख कोशिश करें, मुल्क में एक इंच भी आप आगे नही बढ़ पाएंगे। पश्चिमी बंगाल की मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि वहां 83 फीसदी गरीब लोग जमीन के मालिक हैं, सिर्फ 17 फीसदी ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है। ऐसा proportion मुझे नहीं मालूम कहीं और है या नहीं। जब तक यह तब्दीली नहीं आएगी, तब तक गांव की इकॉनमी में तरक्की नहीं होगी।

हम लोग बंगाल में देखते हैं कि पहले हर साल गांवों के लोग शहरों में आ जाते थे घर-घर में काम करने के लिए, अब उनका आना बंद हो गया है, क्योंकि land reform होने की वजह से गांवों में बहुत किस्म के कारोबार खुल गए हैं और वे वहीं अपनी रोजी-रोटी कमाते है। अब जो शहरों में बड़े लोग है, उनको घरों में काम करने वाले नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं, तो वे कहते हैं कि हम 2,000 रुपए महीना लेंगे, तब काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। एक साहब ने हमसे शिकायत भी की कि आप लोगों की सरकार यहां है, लेकिन हमें काम करने वाला आदमी नहीं मिलता है। तो हमने उनसे कहा कि काम करने वाले लोग, जो गरीबी के मारे यहां आते थे, उनकी गरीबी का इलाज वहीं हो गया है, इसलिए वे शहरों में नहीं आते हैं। आप अगर अपने घर में अपनी पत्नी की मदद करना चाहते हैं, तो खुद बर्तन मांज लिया कीजिए, लेकिन सरकार को दोष मत दीजिए, क्योंकि देश में जब परिवर्तन आएगा, तो इस किस्म के मसाइल पैदा होंगे। इसलिए मैं तो यह समझ रहा हूं कि सरकार के पास अभी भी डेढ़ साल का वक्त है, इन डेढ़ सालों के अंदर अगर इन मसाइल पर सरकार ध्यान दे और कुछ कदम उठाए ...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, conclude. अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद अमीन: सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाए, नहीं तो डेढ़ साल के बाद चुनावों में ये जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, यही मुझे कहना है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you for adhering to time. Now, Shri C. Perumal.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, it was his maiden speech.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It was his maiden speech for this term only.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): But, then, he has taken full time of his Party. Mr. Amin, have you completed your speech?

SHRI MOHAMMED AMIN: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri C. Perumal to speak in Tamil.

SHRI C. PERUMAL (Tamil Nadu)*

Hon'ble Chairman Sir, I would like to thank you for having provided me with an opportunity to speak on Appropriation Bill, 2007.

Ours is an agricultural country with six lakhs villages. Agriculture alone is the livelihood for nearly 70 percent of our population. The Government may claim that enough of funds have been earmarked for growth of agriculure. But the results are not enthusing. There is agricultural crisis due to the improper implementation of schemes and mismanaging of allocated funds for this sector.

For example, the Central Government introduced the massive water shed development programme aiming at conservation of water bodies and soil resources. But it is largely observed that the water shed development programme has failed becauses of poor implementation at the ground level. Hence, I urge upon the Government to achieve agriculture growth with appropriate techniques and technology.

If we take Irrigation for agriculture, it is wanting in many ways, depandence on monsoon and inadequate irrigation facilities hamper agriculture. Only about 40 percent of land under cultivation is irrigated. During 1992-2004 the Central Government had allotted nearly Rs.99,610 crore for 210 major and medium irrigation projects. What had happened is to the contrary. The cultivable land covered across the country went down from 17.79 million hectors to 14.16 hectors. Now the Task Force on Irrigation set up by the Government has said that Rs. 1.66 lakh crore would be required annually for irrigation under the Eleventh Five Year Plan. Though the Government has spend large sums towards irrigation, proper maintenance of existing canals and dams are not there.

The State Governments are over-exploiting the rivers by constructing a number of dams, refusing to provide sufficient water to the riparian states and resorting to inter-state water disputes. The Government must take enough care in recharging the ground water level in all areas. If the State Governments check and control the flow of rivers with monopolistic attitude, the Union Government cannot check the deterioration of irrigation systems in our country. Hence I request the Government to include Water in the central list to avoide inter-state water sharing disputes.

At this juncture, I would like to say that our rivers were free when our country was not a free country. But now, in our free Nation the rivers are like slaves of states and are no more free. This is an ironical situation in our independent India at present.

Let us have look at what is happening in Education sector. I would like to urge upon the Government to increase the volume of education loan for the students. Due to stringent rules and regulations followed by the Banking Sector, currently only three percent of such students

*The speech was originally delivered in Tamil.

applying for loans are getting Education loan. Whereas the number of students who get education loan in all of the Developed countries is approximately 80 percent. So I request the Hon'ble Finance Minister to take necessary efforts to provide education loan to all the students or atleast 50% of the students applying for educational loans to pursue higher studies and professional courses. Banks are denying Education loans to the students from Teacher Training Institutes and B.Ed Colleges. Teacher Training Education has also become costly now. They have to pay higher fees and even capitation fees. hence Teacher Training students must also be given education loan through Banks.

The Central Government earmarks less than 0.5 per of our GDP every year for higher education. Now the Central Government allocate Rs. 91,000 crore for education. I request the Government to increase the allocation for education to Rs. one lakh crore every year. The Government must give more attention to education, because illiteracy is the main cause for the increased level of poverty.

As far as the Health sector is concerned, I am very much disappointed with the Government's poor implementation of Health programmes. According to the recent National Rural Health Mission Report, nearly 8 percent of Primary Health Centres do not have a doctor while nearly 39% are running without a lab technician and about 17.7% without a pharmacist. Every primary health centre must have one medical officer supported by paramedical staff. There is a shortfall of 70.2 percent specialists in community health centres. There is a huge shortage for nurses in these centres. The Central Government appoints only those who have studied in Government nursing school for employment in Government Hospitals as per Nursing Council Act, of 1947. On many occasions, I have brought this matter to the notice of the Government. The nursing students who have studied in private nursing schools must also be eligible for employment in Government Hospitals. This is also another reason for the inadequate staff in the hospitals. hence I request the Government to make necessary arrangement to provide employment to all those who have completed nursing course in private institutions also. I am sorry to say that the Government has failed to implement properly the rural health schemes. Instead of facing the huge challenge to meet the shortfall in rural health infrastructure, there is a needless attempt to extend the period of study for medical education. Hence I urge upon the Union Government to increase fund allocation to Health sector to ensure basic facilities in the Rural Primary Health Centres.

Let me draw the attention of the Central Government to the alarmingly widening gap between rural and urban per capita income. Even the people who moved to urban areas due to unemployment in the farm sector, are becoming unorganized workers with meagre salary in adjacent cities. The Central Government have failed to fix category wise for wages of rural and urban labour to ensure better standard of living. This rural urban divide must be levelled up and the internal migration trend must be arrested. There is a heavy pressure on urban infrastructure due to migration from the rural areas.

I do not know whether our Hon'ble Finance Minister had ever experienced the pain of rural or urban poor atleast in his dreams. I am afraid that might be the cause for not making policy frame works keeping in view the plight of downtrodden and lift them up economically, socially and educationally.

I would like to quote our founder leader and former Chief Minister of Tamilnadu our revolutionary leader Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R. and the guiding star of Dr. Puratchi Thalaivi Amma, His philosophy about the life of the poor is depicted in one of his historical films Nadodi Mannan That is about the rulers.

'O' King! you are just looking at the downtrodden people from the balcony of your luxurious palace.

The people at the balcony of the luxurious palace may not understand the pain and the misery of the poor people.

But I am here with the people as one among them looking at the palace feeling the pulse of the people at the grass root level.

So, I request the Hon'ble Minister to evolve plans and schemes from the common people's point of view.

Why I am saying this because poverty alleviation programmes in our country have not yielded desired results. There are still a large number of people living on Rs. 20.30 per day. A recent study by US based International Food Policy Research Institute says, that even our neighbouring country Bangladesh has fared better than our country in terms of poverty alleviation.

We make tall claims about our economic growth and progress. But it is a moot question whether the benefits have accrued to the poor. There is no increase in the per capita consumption of basic requirements inspite of the economic growth.

In 1990, before the advent of economic reforms the average food consumption of a person in our country was 476 grammes. Now it has comedown to 418 grams. This shows that the economic growth of our country as proudly trumpeted by the Union Government, has not brought about any positive change in the lives of the poor people. In this growth scenario drama, we have been witnessing the suicide deaths of about 1,37,000 farmers during the years between 2001-2007. If the program implementation of various Ministries, including Urban Development and Poverty Alleviation had been executed in a proper manner, we would have achieved adequately what we had targetted.

Hon'ble Chairman, Sir, before I could conclude, I would like to point out that this Government has received a loan from World Bank for the year 2006-2007 which is 169 per cent higher than the loan received in the previous year. It will force us to pay huge amount of GDP to the World Bank towards loan servicing.

So, I request the Government to ensure proper implementation and execution of programmes utilizing properly the allocation for various schemes. The Government should come forward to set up a Committee to monitor each and every project budgeted for and must bring its compliance report to the public. We must ensure that the millions of poor people must get a better deal in the ensuing Budget.

Sir, Mango is grown in a big way in our parts. Mango pulp is being exported from there. To give a pap to their export ventures, export promotion incentives may be given to Mango growers and Mango pulp exporters so that they may contribute to the earning of foreign exchange.

Palm Industries Board that aims at improving the lot of rural poor living on Palm products and rural folks resorting to the hard job of climbing Palm trees must get enough of co-operation from the Central Khadi Board in marketing their products. Palm Board must get increased fund allocation.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude it now Mr. Perumal.

SHRI C. PERUMAL*: Hoganekkal Joint Drinking Water Project that has been pending for long must be taken up and completed at the earliest to provide drinking water to the porched throats of people in Krishnagiri, Dharmapuri and neighbouring districts and towns. The Union Government must get funds for the project from any of the sources like World Bank or IMF or Japanese loan and must complete the project at the earliest.

With this, let me conclude. Thank you.

श्री शरद यादव (बिहार): उपसभापति जी, Supplementary Demands पर जो बहस है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर सभी साथियों ने अपनी बात को गहराई से रखा है। इस देश के किसान हैं, गांव के लोग हैं, शहरी मजदूर हैं, जो परमानेंट कहीं लगे नहीं हैं, पर गांव से रोजगार की तलाश में शहर चले आए हैं। इन सबके बारे में जितने भी वक्ता यहां थे, सबने चिंता जाहिर की है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की गरीबी को मिटाने के लिए या जो कमज़ोर लोग हैं, जो लोग दिक्कत में हैं, उनको सहायता देकर, उनकी ज़िंदगी संवारने का जितना प्रयास होना चाहिए, नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार के पास, इस देश के सारे लोगों की जो आमदनी होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा इन गरीबों के लिए जाता है। मैं आपसे इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले लगभग पैंतीस-सैंतीस साल से इस देश में कोई भी एक उपलब्धि, किसी एक बात पर ही देश गौरव कर सकता है, बाकी तो सब हमने विदेशों से सीखा है या लिया है। इस देश में एक ही उपलब्धि है कि हम भोजन के मामले में, खाने के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। आपके आने के बाद, आपकी सरकार के आने के बाद यह उपलब्धि भी किस तरह से खतरे में आई है, इसका लोगों ने ज़िक्र किया कि आप यहां के किसानों को जो दाम दे रहे हैं, उससे दोगुने दाम देकर ऐसा अनाज मंगा रहे हैं, जो खाने लायक नहीं है, यानी मैं यह नहीं कह रहा हूं उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक सरकार का नहीं, देश में जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वह एन.डी.ए. की सरकार हो, चाहे युनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, इस मामले में हर सरकार ने कुछ न कुछ ताकत दी है इसको बनाए रखने में, लेकिन आपकी सरकार जब से आई है, तो जो फूड सिक्योरिटी है इस देश की, एकमात्र उपलब्धि है, और कोई उपलब्धि नहीं है आपकी। इस सदन में जब मैं खड़ा हूं, तो इसकी एक भी चीज़ आपने पुरुषार्थ से नहीं बनाई। यह माइक है, यह भी बाहर से मंगाया है, यानी विज्ञान की कोई चीज़ नहीं है जिसको आपने पुरुषार्थ से, विज्ञान की तरक्की करके लिया हो, यह सब बाहर से लेकर आप आते हैं, लेकिन जो आत्मनिर्भरता थी हमारी फूड में, खाद्यान्न में, जो एफ.सी.आई. था, यहां अभी कृषि मंत्री जी नहीं हैं। वे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश ने अनाज नहीं दिया, एफ.सी.आई. खरीद कर रहा था, वह खरीद नहीं कर पाया, बिहार ने किया। ...(**व्यवधान**)... सुनिए, मैं भी उसी मंत्रालय में रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जानकारी ठीक कर दूंगा। आपके गुजरात, मध्य प्रदेश में हमारी खरीद ठीक नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अफसर को बुलाकर पूछिए कि क्या पहले भी यहां खरीद नहीं होती थी? जब हम थे, सरकार में, तब यहां थोड़ी बहुत खरीद हुई, वह भी धान की खरीद हुई। लगभग 82 फीसदी हिस्सा अकेले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. से गेहूं आता है और 55 फीसदी धान इस इलाके से खरीदा जाता है, जिन तीनों का नाम मैंने लिया, उनमें से दो जगहें हैं - पंजाब और हरियाणा। हां, हमारे ज़माने में जरूर धान की खरीद सब जगह बढ़ी थी। Even बिहार तक में हमने खरीद कराई थी, तो मेरा इतना निवेदन है कि आपने जो मोनोपोली प्रोक्योरमेंट था, जिसे मोनोपोली प्रोक्योरमेंट नहीं कहा जाता, उसमें आपने इस देश की आई.टी.सी., जो मल्टी-नेशनल कंपनी है, उसको खरीद के लिए आपने बाज़ार में दे दिया। अडानी है, कारगिल है, एशियन व्हीट बोर्ड है, इनको आपने खरीद के लिए अनुमति दे दी। मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता वित्त मंत्री जी, लेकिन यह जो व्यवस्था थी, जिसको कायम करने में लगभग चालीस वर्ष लगे, उसको आपने तोड़ दिया। उसको आपने हिला दिया। आज आपके पास गेहूं का उत्पादन बेहतर है—इस देश के भीतर जो जरूरत है, उसके बराबर है, लेकिन आपकी खरीद कमजोर हो गयी और कमजोरी, साढ़े तीन बरस से जो नीति आपने अपनाई है, उसके चलते हो गयी है। इस प्रकार एक फूड सिक्योरिटी का मामला था, वह तबाह और बर्बाद हो गया। मैं मानता हूं कि आपकी सरकार साझा सरकार है। साझा सरकार के चलते आपकी कांग्रेस पार्टी की संख्या 147 है। आप बाजू के आदमी से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। आप अलग विभाग चला रहे हैं। यानी हर सरकार का हर मंत्री आज़ाद है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपने जो योजना गरीब आदमी को ताकत देने के लिए चलायी है, उस पर मैं अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। साढ़े तीन बरस हो गए हैं। अभी हमारे कामरेड बता रहे थे कि गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल वाले लोगों को जो अनाज देते हैं या एपीएल वालों को देते हैं—इस देश में दो

*The speech was originally delivered in Tamil.

करोड़ लोगों को दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल देते हैं। साढ़े तीन बरस में, जो देश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पर सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए थी। आप इस देश में किसकी चिंता करोगे? आज, यह जो सट्टा बाजार है, उसकी ज्यादा चिंता है। पूरे बाज़ार का ऐसा इंतजाम हो गया है कि सट्टा बाजार में क्या घट गया है, क्या बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर इस देश को बनाने की चिंता करनी है तो देश के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। लेकिन उसके बारे में आपने एक बार भी मीटिंग नहीं बुलायी। उसका इंतज़ाम कैसे हो? सबसे बड़ी समस्या यह है कि गरीब आदमी को ताकत देने के लिए जो पैसा है, वह जब जाता है तो वह पैसा उसके काम में नहीं आ रहा है, उसके उपयोग में नहीं आ रहा है। चारों तरफ उसकी लूट मची हुई है। हर गांव से लेकर दिल्ली तक, चारों तरफ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो, इस देश के गरीबों को जो मदद मिल रही है, उस मदद को बीच में उठा रहे हैं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): ये तो स्वंय मंत्री जी बोलते हैं।

श्री शरद यादव: सरकार बोलने लगे, इससे बड़ी* क्या होगी? सरकार के हाथ में तो सामर्थ्य है, ताकत है।

श्री लालू प्रसाद: आप लोग सहयोग करिए। बीच में बिचौलिया खा जाता है।

श्री शरद यादव: हमारे पास बोलने के सिवा और क्या है? आपको शांति से बात सुननी चाहिए, आप तो ताकतवर हैं। आपके हाथ में ही सामर्थ्य है, आपके हाथ में ही ताकत है। बोलने का, भाषण देने का काम आपका नहीं है, भाषण देने का काम हमारा है। आपका काम एक्शन करने का है, आपका काम ज़मीन पर चीज़ों को उतारने का है। आपका काम राज चलाने का है। राज से हमें इसलिए हटाया कि आप ठीक से वहां पर काम करें। इसलिए जो वित्त मंत्री जी हैं, ये खजाना मंत्री हैं। इनको अगर चिंता है तो उस चिंता को दूर करने के लिए, काम को ज़मीन पर उतारने के लिए क्या आपने कोई प्रयास किया? इस देश में जो पैसा दिल्ली से जा रहा है, हर आदमी कह रहा है कि वह लूटा जा रहा है - चाहे सड़क का हो या इंदिरा आवास का हो। इंदिरा आवास योजना क्या कोई मामूली योजना है, उससे गरीब आदमी को पक्का मकान मिलेगा। उस योजना में लूट हो रही है, उसका कोई मकैनिज्म होना चाहिए, उसका कोई सिस्टम होना चाहिए, उसका कोई तरीका होना चाहिए, रिड्रेसल मकैनिज्म होना चाहिए। देश में गरीब आदमी को मज़बूत करने के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, उसका भी सही उपयोग नहीं हो रहा है। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने श्री अर्जुन सेनगुप्ता की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनायी। उनका कहना है कि 78 परसेंट जो लोग हैं, वे इस देश में बीस रुपए रोज़ पर जी रहे हैं। आपका प्लानिंग कमीशन कहता है कि गरीबी रेखा के नीचे लोग घट गए हैं और अर्जुन सेनगुप्ता, आपकी पार्टी का आदमी कहता है कि 78 परसेंट बीस रुपए पर निर्वाह कर रहे हैं। जो प्लानिंग कमीशन है, वह गरीबों की संख्या को घटाकर बता रहा है और आपकी पार्टी के सदस्य, आपके द्वारा बनायी हुई कमेटी के चेयरमैन, श्री अर्जुन सेनगुप्ता कह रहे हैं कि 78 परसेंट आदमी इस देश में बीस रुपए पर जी रहे हैं। इसका मतलब है कि 60 बरस में गरीबी बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। इसको आपको देखना चाहिए, इसकी तुलना करनी चाहिए। ..(**व्यवधान**).. लालू जी, आप कहिए, मैं यील्ड कर सकता हूं।

श्री लालू प्रसाद: हम केवल यह पूछ रहे हैं कि हमारा रेल बजट भी है, और कितने लोग बोलने वाले हैं? मैं आपको नहीं रोक रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): शरद यादव जी, आप बोलिए, लेकिन जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसकी सही बात है, क्या आपका प्लानिंग कमीशन ठीक कह रहा है? मैं प्रधान मंत्री जी से मिला था तथा जानकारी में लाया था कि गरीबी रेखा के नीचे जो आपका आंकड़ा है तथा जो आपके अफसर हैं, जो उन्होंने पैरामीटर बनाया है वह गलत बनाया है। तो उसको सुधारने का काम करिए और उसको सुधारने का काम आप नहीं कर रहे हैं। उसके पहले ही सरकार की तरफ से जो कमेटी बनी उसके जो चेयरमैन हैं, वह कह रहे हैं कि 78 परसेंट जो गरीब लोग हैं वे बीस रुपया रोज निर्वाह कर रहे हैं। सीधी बात है कि अभी सर्विस टैक्स पर बात चल रही थी। मैं मानता हूं कि इस देश में फिजूलखर्ची का ऐसा तमाशा मचा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं हो सकती। यानी खर्च पर सीमा लगाने का कोई न कोई रास्ता बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अभी जया बच्चन जी बोल रही थीं कि उनके बेटे की शादी में जो पंडित है, जो बाल बनाने वाला है, जो साड़ी देने वाला है यानी पिक एंड चूज किया जा

* Expunged as ordered by the Chair.

रहा है। जो देश में काला धन है जिसके बारे में कामरेड ने कहा और मै अमर सिंह जी से पूछ रहा था कि उन्होंने दो-तीन ही नाम बताए और अगर ज्यादा नाम बतलाते तो मैं ज्यादा नाम बतलाता। तो जो काला धन छिपा हुआ है और यह जिनके पास है उसके लिए आपने पिछले साढ़े तीन वर्ष में क्या प्रयास किए हैं और उन प्रयासों का कोई कारगर नतीजा निकला या नहीं निकला? हां, एक जवाब हमारे पास है क्योंकि जो लोग काले धन वाले हैं? उनके पास अदालत भी हैं, उनके पास अच्छा वकील भी है, वेदांत से लेकर चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हों या और कोई हो जिन्होंने गड़बड़ करके रखी है। मैं सभी के लिए कह रहा है कि जब आप एक नज़र से करोगे तो सारे जो भी लूटखोर लोग हैं, क्योंकि इस देश में बड़ा आदमी वैसे नहीं बनता, वह बगैर चालाकी, बगैर धूर्तता के तो बनता ही नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): शरद जी, जल्दी खत्म कीजिए। ....(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव: आप तो बहुत कम पैसे वाली हैं, आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए। आपके जैसे लोगों को मैं पैसे वाला नहीं मानता। ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): आगे देखो, पीछे मत देखो। ...(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव: तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की गरीबी मिटाने का या इस देश को बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि हम खेत से पानी को जोड़ें, जो अभी ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰ के सदस्य कह रहे थे। तो जहां हम पानी ले गए हैं उससे उस देश की सूरत और सीरत बदली है, वहां के इंसान के चेहरे पर पानी भी आया है, लेकिन हमने यानी इस देश के नदियों के मामले को ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इसको स्टेट लिस्ट में—कनकरंट लिस्ट में रख दिया। और नतीजा यह है कि आज नहीं तो कल, इस देश के टूटने का इंतजाम होगा तो इसी रास्ते से होगा, चारों तरफ झगड़ा चला हुआ है, चारों तरफ लड़ाई चली हुई है। हालांकि यह मामला आपका नहीं है लेकिन सरकार में आप हैं। इस पर चिंतन होना चाहिए कि नदी जोड़ेंगे तो या नदी नहीं जोड़ेंगे तो, या कोई और जितने भी खेत में पानी ले जाने के प्रकल्प हैं, वे सब के सब ठप्प हैं, बर्बाद हैं। तो उस चीज को हाथ में लेना चाहिए और गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं, उसके लिए यहां सारे मुख्य मंत्रियों को बुलाइए, सारी पार्टियों को बुलाइए और युद्ध स्तर पर यह कार्य करने का प्रयास करिए, क्योंकि 60 वर्ष हो गए, गरीबी बढ़ रही है, यह आपकी पार्टी का आदमी कह रहा है। यहां गरीबी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है और यह देश बेचैनी और हर तरह के रंज और अफसोस में है। विज्युअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना बढ़ गया है कि इधर-उधर से हर चीज की खबर रोज आ जाती है। पूरा देश एक तरह से बेचैन है और उस बेचैनी के साथ क्या हमारे चहरे पर जरा भी शिकन न आए? मैं आपकी पार्टी और आपकी सरकार के मंत्रियों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सब काम उन्होंने पूरा कर दिया है। सारे चेहरे संतुष्ट हैं, सब बिल्कुल संतृप्त हैं। क्या इस देश के जिम्मेदारी वाले आदमी के चेहरे पर संतुष्टि हो सकती है यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कंगाल और सबसे ज्यादा गरीब लोग यहां रहते हैं इस देश का जो सबसे ज्यादा शानदार पत्रकार साईनाथ कहता है कि हर तीन मिनट के बाद इस देश में एक किसान की मृत्यु हो रही है। हम सब लोग चाहे हम हों या आप हों, हमको इसकी चिंता ऐसी करनी चाहिए कि इसके लिए युद्ध करना चाहिए और युद्ध करके इस देश में इन समस्याओं का निदान निकालना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों के लिए आप मीटिंग बुलाइए, कोई सम्मेलन बुलाइए और उसके लिए कोई प्रयास करिए तथा देश को बनाने का काम करिए तब जाकर काम चलेगा और तब कहीं आपके यहां बैठने की सार्थकता होगी।

श्री मंगनी लाल मंडल: धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Sir Mangani Lal Mandal. There is time constraint before me. That is why I am saying this. Your party has got seven minutes. Try to conclude within seven minutes.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: This is a very important subject, Sir. Let them speak. They are all speaking very well. There are very few Members in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Members should know that I have to go by the time allotted. Teh time allotted is four hours. Each party has been allotted the time. Mr. Sharad Yadav had four minutes. But he spoke for 13 minutes. You understand it. If I allow you more time, you have to sit late in the night. ...*(Interruptions)*... No. I permitted.

...(Interruptions)... She was raising it again and again. That is why I am saying this. *...(Interruptions)*... I have to control the House, not you. This is not the way.

श्री शरद यादव: सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। इस सदन में हम 33 वर्ष से हैं, बहुत कम लोग हमारे बराबर के हैं। मैं आपसे कहूं कि पहले भी सदन चलते थे, आप तो सदन के मालिक हैं। बहस को आप जितनी गहराई तक जमायेंगे, उतना ही सदन के सदस्यों पर असर होगा और उस असर का पूरे देश पर असर होगा। ...(**व्यवधान**)...

SHRI VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): In fact, I really wanted to give you more time.

श्री शरद यादव: सर, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर हमें वक्त मिलता, तो जो बात हमने ऊपर-ऊपर कह दी, जरूर सबकी संवेदना के साथ यह जुड़ने का काम करती। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I was also listening to your speech and I wanted to give you more time.

श्री लालू प्रसाद : सर, एक बात मेरी सुन लीजिए। मैं शरद जी की बातों से सहमत हूं। लेकिन इनको यह भी सोचना चाहिए कि जो भी समय और सत्र चला, कितना समय का नुकसान इन लोगों ने किया, कितना block किया, कितनी बहस हुई गरीबी, गुरबत, लाचारी पर, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। महोदय, इस बिल के बाद में, हमारे रेलवे का सप्लीमेंट्री बिल भी है, उस पर भी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि संक्षिप्त में एक बात को कनक्लूड करवाइये।

श्री राहुल बजाज: सर, हमारे जैसे सांसदों को भी बोलने का समय मिलना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): प्लीज सुनिए। We have to complete it in four hours. There are 12 more speakers. That is my problem and everybody should be given time. Yet, every party is taking more time than that is allotted.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मेरा आग्रह है कि बजाज साहब को बोलने दिया जाए, ताकि गरीबों की सही चिंता सदन के सामने आ सके।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): मंगनी लाल मंडल जी, अब आप बोलिए।

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): सर, मेरा अब समय प्रारम्भ हुआ है, पहले जब आपने बुलाया था, उस समय से नहीं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान की पूरक मांगों के लिए विनियोग विधेयक आया है, मैं आनी पार्टी की ओर से उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मुझे कुछ शंकाएं हैं। सरकार दावा कर रही है कि 9 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... मेरी कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं का मैं समाधान प्राप्त करना चाहूंगा। यह बात सही है कि तरक्की हो रही है, विकास दर की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन दो-तीन बिंदुओं पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह मेरी शंकाओं का समाधान करें। यह द्वितीय पूरक है, प्रथम पूरक 20412.14 करोड़ रुपये का था, यह द्वितीय जो पूरक है 42 अनुदानों के लिए, यह 33290.87 रुपये का है, ये दोनों मिलाकर के 53703.01 करोड़ रुपया होता है। मतलब यह है कि जो मूल बजट था, वह मूल बजट था 680581 करोड़ रुपये का, अगर इसमें दोनों सप्लीमेंट्री को जोड़ दिया जाये, तो यह कुल बजट अब तक का हो जाता है 734224.01 करोड़ रुपये का पूरा बजट हो जाता है। संवैधानिक व्यवस्था है कि सप्लीमेंट्री बजट आयेगा, यह कोई नयी बात नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्री बजट आयेगा, तो इसमें प्लान हैड में और नॉन प्लान हैड में, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। जहां हम प्लान हैड में 2571.11 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में 17841.03 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, ये जो दो विनियोग विधेयक पेश किए गए हैं, हम अपनी पार्टी की ओर से इनका समर्थन करते हैं। महोदय, एक बात यह है कि इंडिया के दो चेहरे हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। यहां पर शिक्षा और कुपोषण दोनों बढ़ रहे हैं। इस देश में जो बड़े इजारेदार हैं, सरमाएदार हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है, किंतु लोगों को कॉरपोरेट सैक्टर में ज्यादा छूट मिली है। करदाताओं के मामले में, लेकिन जहां 2003-2004 में 2,88,01,1548 लोग टैक्स पेयर्स थे, वहीं से 2006-07 में बढ़कर 2,97,97,914 लोग बढ़े हैं। हम इसमें दो बाते जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में 45 लाख लोगों ने 2006-07 में रिटर्न्स फाइल नहीं किया है और इसके विपरीत किस परिस्थिति में सिर्फ 9 लाख एसेसी बढ़े हैं, जो एसेसमेंट की संख्या बढ़ी

1.00 P.M.

है, उसके मुकाबले में 2 करोड़, 97 लाख, 97 हजार, 9 सौ 14 के मुकाबले में 2 करोड़ 54 लाख, 19 हजार, 5 सौ 53 लोगों ने कम्पलाइन्स किया है। मैं एक बिन्दु पर यह जानना चाहूंगा कि जो टैक्स एसेसमेंट होता है, उसमें नॉन कम्पलाइन्स करने वालों की संख्या जो 43 लाख, 78 हजार, 3 सौ 79 है और सिर्फ 9 लाख, 2003-04 के मुकाबले में 2006-07 में बढ़ा है, मैं इस मामले की स्थिति जानना चाहूंगा।

महोदय, जो दूसरी सबसे बड़ी स्थिति FDI के मामले में है कि FDI हिन्दुस्तान में बड़ी तेजी से आ रहा है, लेकिन हमारा मुकाबला चीन से है। कहा जाता है कि जो चीन में FDI के माध्यम से पैसा इंवेस्ट करने वाले लोग हैं, चाहे जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे दुनिया के अन्य देश हों, सारे देशों के लोग इंडिया के मुकाबले में चीन को प्रेफर करते हैं। वे चीन को इसीलिए प्रेफर करते हैं कि जो आधारभूत संरचना है, वह आधारभूत संरचना इंडिया के मुकाबले चीन में ज्यादा सुदृढ़ है। अभी जो ग्लोबल कम्पेटेटिव इंडेक्स 2007 प्रकाशित हुआ है, उसमें इंडिया आधारभूत संरचना में जहां 6 पायदान सरक कर नीचे चला आया है, और अभी 48वें स्थान पर चला गया है, इसके विपरीत चीन एक पायदान ऊपर खिसक कर, 34वें स्थान पर चला गया है। यह जो बुनियादी और ढांचागत सुविधा है, उसके मुकाबले में हमारे यहां FDI का पैसा चीन के मुकाबले में कम आ रहा है। जहां 2004 में 5 हजार, 7 सौ, 71 मिलियन अमेरिकन डालर हमारे यहां आया, यह बढ़ा जरूर है, यह 2006 में 16 हजार, 8 सौ, 81 अमेरिकन मिलियन डालर बढ़ा है। इसके विपरीत चीन की स्थिति इससे बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि जहां 2004 में चीन में 60 हजार, 6 सौ 3 मिलियन अमेरिकन डालर का FDI हुआ, वहीं यह बढ़कर 2006 में 69 हजार, 4 सौ, 48 अमेरिकन मिलियन डालर हुआ। कहने का मतलब यह है कि चीन के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं और बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में देश में विकास दर सितम्बर, 07 से पहले 10.4 फीसदी थी, वह घटकर मात्र 6 फीसदी रह गयी है। अगर हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं, तो जो बुनियादी ढांचे में गिरावट आ रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। महोदय, मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूंगा कि रूरल और अर्बन में जो अंतर है, वह बढ़ता जा रहा है। जो हमारी योजना है, प्लानिंग है, उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन गांव और शहर में भी अंतर बढ़ रहा है। जहां 1970-71 में जो रेश्यो था, वह रूरल की इनकम का 529 रुपए था और अर्बन का 1294 रुपए था। जो 1999-2000 तक का आंकड़ा है, उसमें 10 हजार 600 हो गया है, रूरल का है। शहरी लोगों की आमदनी तीन गुना बढ़ गई है। शहरी लोगों की आमदनी बढ़कर 30,217 रुपए हो गई है। यह जो अरबन और रूरल का अंतर बढ़ रहा है, इस अंतर को पाटने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। एफ.डी.आई. का पैसा कम आ रहा है, लेकिन पैसे की वृद्धि, जिसकी चर्चा सभी लोगों ने की है, हमारे यहां पैसों की बरसात हो रही है, इसके साथ-साथ हमारा जो एक्सटर्नलन डेट है, वह हमारा डेट बढ़ रहा है। ...(**व्यवधान**)... जो एक्सटर्नल डेट long term था, वह मार्च, 2005 में 116.7 यू.एस. बिलियन डॉलर ...(**व्यवधान**)... वह जून में 2007 में ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mandalji, one second please. It is 1.00 p.m. I believe, it is the consensus of the House that we will not have the lunch break.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Why, Sir? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Because we have to finish it ...*(Interruptions)*... So, agreed. No lunch break today. Mandalji, please continue.

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, जो एक्सटर्नल डेट था, वह बढ़कर 152.4 यू.एस. बिलियन डॉलर हो गया है, जो मार्च, 2005 में short term था, 7.5 यू.एस. बिलियन डॉलर, वह बढ़कर 13.3 हो गया है। मतलब, हमारा जो बाह्य ऋण है, वह कुल मिलाकर आज की तारीख में 165.4 बिलियन डॉलर है। एक स्थिति यह भी है। हम जो बाहर से ऋण ले रहे हैं, यह बजट का है, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि बृजभूषण तिवारी जी और अन्य सदस्यों ने कृषि के मामले में चर्चा की है। स्वामीनाथन आयोग ने कृषि पर एक व्यापक प्रतिवेदन सरकार को दिया है। इस सदन में चर्चा नहीं हुई है। इन्होंने कई बिंदुओं पर होर्टिकल्चर से लेकर एग्रीकल्चर की जितनी तमाम अलॉयड एक्टिविटीज हैं, उन पर व्यापक प्रतिवेदन दिया है। जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की घंटी है, वह यह है कि 2021 तक हमने जो लक्ष्य रखा है, वह 29 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करने के लिए रखा है। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए हैं, यह बात गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और 4 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य अगर ग्यारहवीं

पंचवर्षीय योजना में हासिल नहीं होगा तो 2021 तक 29 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से जो खाद्य सुरक्षा है, वह खतरे में पड़ जाएगी। अत: इन बिंदुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं इस बजट, इन अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं ओर मानता हूं कि साढ़े तीन वर्षों में सरकार ने काफी तरक्की की है। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है। एन.डी.ए. सरकार के मुकाबले इस सरकार की विकास दर काफी तेज़ है। धन्यवाद।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I thank you very much for permitting me to speak on the Appropriation (No. 4) Bill, 2007 and the Appropriation (No. 5) Bill, 2007. Sir, I start with saying that in the post-reforms era, certainly, wealth is created in the country. But, unfortunately, it is confined to only a few people and it has got no trickle down effect to the common man. Sir, the main thrust of the NCMP is on *aam aadmi*. I don't know why the Government is not concentrating on providing facilities like employment, health and education to the *aam aadmi,* the so-called *aam aadmi,* according to the NCMP. Sir, the present reform process has yielded good results, but it has brudened the common man. Sir, I dare to say that the Government is pampering the corporates and pauperising the masses. Sir, the Government's priorities are like displaced development and misplaced priority. Sir, I would like to stress this point since the Budget is increasing year after year. I would like to quote one answer which is provided to me by the Government. In 2004-05, the food subsidy was Rs. 25,746 crores. In 2005-06, the food subsidy came down to Rs. 23,071 crores. Sir, in 2006-07, it is Rs. 23,827 crores. When the Budget is increased, revenue is increased, why this reduction in subsidy? Sir, this is the answer given to me by the hon. Agriculture Minister on 23rd November, for a Starred Question No. 129 in this august House. What is the priority? That is why I say, yours is a displaced development and misplaced priority. I want to stress this point.

Sir, the Government is concentrating on political vendetta. I am shocked to hear that Government chose to derive pleasure out of giving notices to my senior colleague of UNPA, Smt. Jaya Bachchan, to a priest, a florist! What is this, Sir? The Government should concentrate on developmental activity, not on petty things. Sir, this is the attitude of the Government. Then, what will be the fate of a common man in the country? I would like the hon.Minister to enlighten us on why you are importing foodgrains from other countries.

Sir, there is agitation taking place everywhere in the country. Take any State-Andhra Pradesh, Maharashtra. West Bengal. Everywhere there is an agitation by the farmers and on behalf of farmers, demanding minimum support price for paddy. We are demanding at least Rs. 1,000 support price for paddy at par with wheat. You are denying that! Sir, the rise factor, investment and the yield, when compared with wheat, the paddy-growing farmer is on a different footing. There is a partisan attitude and I would like to draw the attention of the hon. Minister on this.

Where is the mechanism for you to check the proper utilisation of funds? Sir, I will quote one example. Yesterday, there was a news item from Andhra Pradesh wherein a person came on a TV channel saying that he needed police protection since he had threat from a person who was working in hon. Chief Minister's office! He had drawn Rs. 15 crores out of the DPEP funds! Sir, an amount of Rs. 15 crores is swallowed! There is a big scam in DPEP in Andhra Pradesh. Sir, I do not know what happens to the Government; no inquiry and nothing. The Government of India is sitting pretty well and left the entire investigation to the State Government wherein the prime accused is working in hon. Chief Minister's office! He stands exactly behind the Chief Minister, wherever he goes! He is the prime accused. The person who is charged with the case is on record saying that he needed police protection.

Sir, the money is given by Government of India. Where is the mechanism to check misuse and diversion of funds? Rs. 15 crores was meant for school education. That money is collected through the 2% cess. Is it not the duty of the Government of India to inquire in detail and take some action? I understand your compulsion since he belongs to your party. This is the partisan attitude adopted by the Government of India. *(Time-bell)*

Sir, the other subject is SEZs. You are forcing SEZs on farmers. I would call SEZ as Special Exploitation Zone, rather, Special Encroachment Zonel ! Sir, I have with me an answer from the hon. Agriculture Minister, again. This is placed yesterday. This is also a Starred Question, wherein it is stated that on an average 18,000 to 20,000 farmers are committing suicide. This is only the reported cases. The unreported cases may be many. When such is the situation of agriculture, why are you taxing them? Where is the subsidy going? You are giving subsidy to the fertilizer industry. Why not you give subsidy directly to the farmer? Sir, is it reaching the farmer? Why do not you have some introspection?

I now come to your NREGP and the flagship programmes like Bharat Nirman. About NREGP, I would like to request the hon. Minister to at least find some time to go through the Social Audit Report. Lakhs of money is being diverted or misused or swallowed. I request the hon. Minister to have some time to go into the reports of Social Audit Report under NREGP.

Take your triple 'R'. Triple 'R' is a very good programme. When we heard you during Budget Speech, I was very happy. Sir, I come from rural area. I was Sarpanch of a village. After that I served in the Assembly. I was pretty happy when you thought of triple 'R' — restoration, renovation and repair of age-old tanks. Now , practically nothing is taking place at the lower-level. Have some mechanism. Sir, the other programme is Mid Day Meal. Sir, it is a very good programme started during the other regime. I would like to request the hon. Minister to have the programme for the Xth Class students also. Since the programme is for Vth, VIth, VIIth and VIIIth standards, if there is a High School, the IXth class and Xth Class students have to go out during lunchtime. It is very difficult for them to have lunch outside. Sir, I would like to request the Minister to extend it to Xth Class students also.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Good point.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Are you mentioning Mid-day Meal Scheme ? ...*(Interruptions)*... The Mid-day Meal Scheme was started by the UPA Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: No, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: I will give you the figures. You complete your speech. ..*(Interruptions)*..

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I stand corrected. ...*(Interruptions)*... The other point is regarding migration from rural areas to urban areas. Sir, it is very difficult becasue as of now, I am told, 30 per cent ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN: (PROF P.J. KURIEN): Do not go to new points. ...*(Interruptions)*... Already you have made very good points. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Equally, Sir, I have to answer enough points. .. *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Time constraints. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: So many problems are there, Sir. This is the occasion to have some introspection.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, I have understood. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I would like to know from the hon. Minister regarding migration. Already 30 per cent of our population is in urban areas. Sir, I am told by 2020 it is going to be 45 to 50 per cent. Sir, wehre is the men and material with the local bodies in urban areas? You need water, you need shelter, you need sanitation, you need power, etc. You concentrate on that aspect also. You try to provide facilities to the rural areas. (*Time-bell*) Why the rural masses are migrating to the urban areas, we should have a detailed study on this. It is for the education of their children, in search of employment, for better health facilities that they are migrating. Why don't you provide those facilities so that people remain in the rural areas? Otherwise, it is going to be a big problem in the urban areas. ...*(Interruptions)*... Sir, only one last point. ...*(Interruptions)*... Yesterday we went to the organic agriculture *mela*. You are providing subsidies to the fertiliser companies, for pesticides and all those things. Sir, why don't you encourage organic farming? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, more than 2000 farmers are engaged in organic farming in Warangal District of Andhra Pradesh. Sir, where is the encouragement for them? Try to encourage organic farming which is helpful not only to the farmers but also to the people because it is the healthiest food also. And it will definitely help in boosting the agriculture in organic farming. Thank you.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Sir, permit me to confine myself basically to some issues of policies.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Becuase of time constraints, please, be brief. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: I will be as brief as possible. But let me first say that I rise to congratulate the Finance Minister. He has done a wonderful job. Our economy is growing at a very high rate and the substantial part of credit should go to his policies. But it should also be noted that this particular high rate of growth is appreciated by Mr. Agarwal, the representative of the BJP. I have no adverse comment except that similar high rate of growth was achieved also during Yashwant Sinha's time. I think our Finance Minister will have to differentiate his product from the previous achievement of Yashwant Sinha. What is the best way how he can do it is to make it very clear that this rate of growth is going to help the *aam aadami*, the issue on which the party fought the election and really defeated the previous Government, that the growth is not only for the sake of growth but also for the *aam aadami*. If you want to do *aam aadami*-oriented growth, what is the most important thing is that you have to have specific targeted policies for the poor and the downtrodden. What we have seen, again and again, in all our experience, that the general policy for growth does not tricle down so fast to the poorest of the poor, unless you have very targeted policies. If you want to have targeted policies, you will have to have expenditure and will also have to have methods of deliverying it. I read Mr. Finance Minister's speech in Lok Sabha yesterday. He

raises this question, again and again, and very rightly so that he is not very sure whether all the money that he has provided for the social programmes will be actually delivered. He talks about the governance. It is a very major issue. But, unfortunately, this issue has to be tackled by him. He is a part of the Government. He has to sit with other members of the Government to see that these policies, these particular programmes are delivered. In fact, there are certain programmes which have been delivered very well. I would say that some States have done extremely well with regard to the National Rural Employment Guarantee Scheme. Some States could not do it. The programme of Dr. Anbumani Ramdoss — the National Rural Health Mission — is one of the best programmes that has been adopted. All that I am saying is that it is important that we should be able to work out a method of monitoring and see that delivery is made. So, this is not just a question of excuse. Governance is the responsibility of the Government and I hope Mr. Chidambaram will take it up in his reply. The question that will come is that if you are willing to deliver the programmes, you have to provide finance and that finance would require, probably, some subsidy. I am not saying all the time to give subsidy. But you have to provide for some expenditure. Now, we have to consider whether it is feasible or not. I would like to consider this very carefully. Subsidy should not be rampant. Expenditure must be efficient. But, then, you have to choose between subsidies. You cannot completely withdraw all the subsidies. It is a question of which subsidies you would, actually, provide. I would come to this point immediately about the possible criteria. But the question is, if you have to provide subsidy, if you have to provide for expenditure, you have to provide finance for which you have to raise revenue. Now, it is true, this is a very impressive performance of this Government that our revenue has increased very substantially. But, by any calculation, a very few people would deny that, if all our taxable individuals or households paid their taxes, the total revenue would quadruple.It will increase four times. The fact of the matter is that most of our taxable people do not pay taxes. Now, how it sould be done? It is, again, the hon. Finance Minister's responsibility how to increase the tax net. But, suppose taxes cannot be raised, then there is a choice whether you would give up these programmes, programmes which are necessary for *aam aadmi* or you will increase a little bit of deficit financing. I am putting this point very clearly. I am not in favour of deficit financing. But, if the choice is that you have no way you can increase the revenue, then the trade off can not be that you reduce this expenditure on *aam aadmi* programme. You have to raise the deficit. And, if deficit is raised by 0.5 per cent or even 1 per cent of the GDP, its total effect on the economy would be marginal. I raised this point earlier in the last session that we should not make a fetish of no deficit at all.

Next question that will come is how do we prioritise between the different subsidies. The first point, besides the question of expenditure on the *aam aadmi* programmes, the question come about the prices. Sir, I must mention that this Government will stand or fall on its ability to control prices for the poor people. The question is not just inflation of the WPI. In fact, in terms of the WPI, the inflation is controlled. It is hardly 3 per cent. But for common man's product, the Consumer Price Index is 7 per cent. It is more than double! And, you have to do something to control it. That is what affect the common people. How to control that? Mr. Finance Minister has mentioned that there are two sides —demand and supply. It is very correct. He said that supply side problem is very difficult here, because the production is not increasing at a fast rate. I am afraid, that issue is a long-term issue. The immediate issue is, how, within the given production, you can have more supply for the common people. The only way to do that is to expand the Public Distribution System. In other words, you have to have a Public Distribution System, which will give the essential consumer goods at the

cheapest prices. (*Time-bell*) For that, subsidy would be necessary, and that subsidy you will have to be able to incur. I am mentioning this because the PDS, unfortunately, has been very much curtailed just to get. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please try to conclude.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Sir, I want just a few minutes more because I want to make some major point just for the sake of people. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, you can take two minutes more.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Okay, Sir. The PDS has actually been curtailed. It should be a policy that the PDS must expand, for which we have to procure more food, either through increasing the MSPs, which this Government has done, or through allowing the FCI to go to the market and buy from the famers at the market price.

Now, I come to imports. 'Imports' is not a bad thing, if it is meant for buffer-stocks. It does not affect the producers price. It is for the PDS system. And, for that import should be done if necessary. The only problem is that this import should be through a mechanism. It should not be off and on; you enter the market when the prices are high and get out of the market when the prices are low. The Finance Minister is aware of this kind of problem. We have machineries by which we can take the future price on the ...*(Interruptions)* The only thing is that the decision will have to be taken. A permanent machinery has to be set up to have that kind of imports.

Now, I come to my final point. This point has not been mentioned yet. The main reason of inflation, in India, today, is the increase in money supply. And, the increase in money supply has been very largely due to an excess inflow of foreign investment. The FII, in this country, has caused a substantial increase in the money supply. Any attempt to ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Senguptaji, you are been very good points, but I am unable to ...*(Interruptions)*

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: I will conclude soon, Sir. I was mentioning this point because I hope the Finance Minister will combat this excess money supply. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude. *(Interruptions)*

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Just one second, Sir. If you would try to control that by rate of interest, which the Reserve Bank tries to do, the result of that would have a very definite effect of our industrial production, which is happening now. If you look at the industrial production, now, over this period when there is an increase in the interest rates, the industrial production rate has come down. If you do not do that, the rupee value will appreciate, dollar will fall and your exports will decline. And, that export decline, unfortunately, will hit mostly the small exporters because they are people who export mostly from the indigenous product. They do not have the benefit of lower cost of imports. *(Interruptions)* The lower cost of imports also — because if the rupee goes up, the prices will be cheaper — will hurt the poor producers. The Chinese products are flooding the market. I am not saying that you should stop that. But you should realise that when they are flooded in the market, most of the alternative producers. *(Interruptions)* So, this effect of the FII has to be controlled. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please conclude. *(Interruptions)*

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Just a minute, Sir. That FII control — I want the Finance Minister to respond to it, if he wants — has an international policy. There, you put a tax, the Tobin tax, on the FII inflow. The 'Tobin tax' is not the exact term, it is Tobin-like tax. The Tobin tax is, when all the countries put the tax. But the Tobin-like tax, which Malaysia has done, Chile has done, Argentina has done. It is a tax when you impose the tax on inflow, not on the outflow. If you want to take the capital out, that is a different issue. But on the capital coming in, you put a tax. That is a method of controlling the FII. I would like to know from the Finance Minister whether he is contemplating a policy, by which the FII inflow can be controlled. As a result of that, the effect of rupee is managed because if the rupee value increases, as the dollar value declines, it will be increasing imports and hurting the exports. It is also hurting the small domestic producers of exportable and import competing products. *(Time-bell)* Thank you very much, Sir.

कुमारी निर्मला देशपांडे (नाम-निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं यहां कुछ बुनियादी बातें रखना चाहती हूं। आज देश में जो आर्थिक विकास हो रहा है, उसके लिए वित्त मंत्रालय बधाई का पात्र है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं कि अंतिम दिनों में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लोक सभा में एक भाषण दिया था, जिसकी प्रतिलिपि यहां उपलब्ध होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन आर्थिक नीति के बारे में हमने गांधी जी के सिद्धांतों को नहीं अपनाया, इसलिए आज हमें बहुत सी समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा है। यह जो उनकी एक किस्म की अंतिम चेतावनी थी, उसकी तरफ मैं माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

महोदय, इसी के साथ जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो पूंजीवादी देशों में बड़ी खुशियां मनाई गईं, लेकिन मुझे याद आई महाभारत की वह कहानी, जिसमें लड़ाई के बाद भगवान कृष्ण गांधारी के पास सांत्वना देने के लिए गए, क्योंकि उनके सभी पुत्र मर गए थे। उस वक्त गांधारी ने कहा था कि हे यदुपति, मेरे तो पुत्र मर ही गए हैं, लेकिन क्या तेरे यादव भी सुरक्षित रहने वाले हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा - माता जी, मैं जानता हूं कि उनका भी वही हाल होगा। यह सोवियत इकोनोमी का, जो एक तरह से पतन हुआ, लेकिन क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टिकने वाली है? यह एक बुनियादी सवाल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अभी हमारे साथी अर्जुन कुमार सेनगुप्त जी बोले हैं। उन्होंने अमरीका में गरीबी पर एक सर्वेक्षण किया और ऐसे चौकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए कि वहां गरीबी अंडर द कारपेट है, परन्तु बहुत गरीबी है। हमने वहां भी इसको देखा है कि सूप किचेन में जो बेरोजगार और भूखे लोग आते हैं, वे कौन लोग आते हैं? इस बारे में मैंने वहां पूछा कि क्या काले और सांवले लोग आते हैं? तो चलाने वालों ने कहा कि जी नहीं, ज्यादा गोरे आते हैं। सवाल यह है कि वहां जो यह गरीबी है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर प्रश्न-चिह्न लगा रही है। इसलिए इस वक्त भारत को चाहिए कि जरा मुड़ कर देखे कि गांधी जी ने क्या कहा था और क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था में उन सिद्धांतों को लाकर एक नई अर्थव्यवस्था प्रस्तुत कर सकते हैं? एक दूसरा प्रश्न चिह्न लगा है वर्ल्ड सोशल फोरम, और जिसका उद्देश्य है एनादर वर्ल्ड इज पोसिबल, लेकिन वह कैसे होगा? नई दुनिया तब बन सकती है, जब नए किस्म की अर्थव्यवस्था लागू की जाएगी। क्या गांधी जी का भारत इसमें पहल नहीं करेगा?

महोदय, इसी के साथ एक और बुनियादी समस्या मैं रखना चाहती हूं। जब हम पाकिस्तान जाते हैं, तो आम आदमी हमसे कहता है कि इधर भी गुरबत है, उधर भी गुरबत है, इधर भी बेरोजगारी है, उधर भी बेरोजगारी है, इधर भी शिक्षा और दवा की कमी है, उधर भी कमी है, तो हम क्यों डिफेन्स के नाम पर, प्रतिरक्षा पर इतना खर्चा कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने तालुकात अच्छे करते हैं? क्यों न हम इस तरह की दोस्ती और अमन का माहौल पैदा करें, ताकि दोनों देशों का डिफेन्स पर होने वाला खर्चा कम हो जाए? तो इस दिशा में क्या हम सोचने वाले हैं? इसी के साथ मेरे एक साथी ने जो बात कही कि भूमि समस्या की तरफ, लैंड प्रोब्लम की तरफ इधर कई सालों से लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया है। मेरे जैसे, आचार्य विनोबा जी के साथ भू-आंदोलन में हजारों मील चलने वाले कार्यकर्ता भी अपने आपको कसूरवार मानते हैं कि भूमि समस्या के हल के लिए जिस किस्म के अहिंसात्मक आंदोलन करने चाहिए थे, उसमें हमने भी कोताही की है। इसलिए मैं इसकी तरफ सरकार का जरूर ध्यान दिलाना चाहती हूं।

महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि गरीब को यह महसूस होता था कि मेरे लिये काम किया जा रहा है। आज क्या यह गरीब को महसूस हो रहा है? इस पर भी हम लोग सोचें। अंत में मैं इकबाल साहब का एक शेर पढ़कर खत्म करूंगी-

बुलन्द वादों के सहारे हम कहां तक जिया करेंगे।

हमें हमारी जमीन दो, हम आसमां ले के क्या करेंगे।

जय जगत।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the two Bills proposed by the hon. Finance Minister but with a rider. The scope of the discussion, I understand, is to have a brief review of the performance of the Government and suggest mid-course corrections, amendments by the Government as far as the economic policies are concerned. It is true that certain economic factors may please the hon. Finance Minister and the Government, particularly, the growth of GDP at the rate of 9.1 per cent or 9.2 per cent, or, the increase in exports. All these factors may please him or please the Congress Party, but, definitely, the Human Development Indicators are not encouraging, and they cannot please the hon. Finance Minister, or, the Congress Party. In our own House, we have Shri Arjun Sengupta and we have Shri Swaminathan; their reports are enough to tell the Government, "All is not well", and the Government will have to make some serious introspection to go for some mid-course corrections. It is true that the BJP has realised certain things now; that was why they were talking about poverty. I am happy about that. *(Interruptions)*... At least, you are talking about poverty. But when you were in the Government, when farmers were committing suicides in thousands, you were claiming 'India shining'. Now, you are talking about poverty. I am happy about that. Sir, poverty is one thing which has ...*(Interruptions)*...

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): Farmers बहुत पहले से आत्महत्या कर रहे हैं।

SHRI D. RAJA: When you were in power, they were committing suicides, but you were claiming India shining. Finally, what happened? You did not care for the India which is suffering. *(Interruptions)*...

श्री कलराज मिश्र: कहेंगे तो इतिहास से उत्तर मिलेगा और अच्छा उत्तर मिलेगा। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, please..*(Interruptions)*..

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): आपने क्या किया, जरा अपने गिरेबान में झांककर देख लीजिए। ..(**व्यवधान**).. What have you done in the last two, three years? *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): See, we have shortage of time. *(Interruptions)*...

श्री कलराज मिश्र: बात कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Raja, don't say anything controversial. Speak only on the Budget. Mr. Raja, please speak on the Budget only. We have shortage of time ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र लाठ: एक बार अपने गिरेबान में झांककर देख लीजिए।

SHRI D. RAJA: Sir, I am speaking on the Budget. Since there was a reference from their side to the Left, I am responding to that. *(Interruptions)*

श्री सुरेन्द्र लाठ: NDA सरकार की बात करने से पहले, अपने गिरेबान में झांककर देख लीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI D. RAJA: There was a reference from your side to the Left, I am responding to that. ...*(Interruptions)*... If you do not want to listen to me, it is your problem. *(Interruptions)*...

श्री कलराज मिश्र: यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान)... इस तरह से बीजेपी के बारे में ...(व्यवधान)... ठेकेदार हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI D. RAJA: Sir, I said, I am happy that *(Interruptions)*... Let me speak. Sir, I am genuinely concerned with poverty; that is why, I am speaking. Sir, I start from where Shri Arjun Sengupta left. The international monetary situation is very volatile. There is a decline in the value of dollar and there is a big inflow of Foreign Institutional Investments. You will find that there is a big wayward behaviour in stock exchange. I think the stock exchange, or, the sensex points rising should not influence the thinking of the hon. Finance Minister or the Government. In fact, the social realities, the economic realities of the country and the living conditions of the people must influence the policies of the Government. And, here, I must say that agriculture really stands neglected. Even though we are an agrarian country, the contribution of agriculture to economy is just 18 per cent, for which we all must think seriously, and farmers must be liberated from indebtedness. That is the root cause for suicides. Farmers must bet remunerative prices. Our agriculture must become a remunerative one. Here, I must ask the Government to think of how the Government can help the paddy cultivating farmers, because they are all asking for the Minimum Support Price. If farmers get the Minimum Support Price or the Remunerative Price, then, there can be an increase in our agricultural production. That can put an end to our dependence on import of foodgrains from foreign countries also. This has to be taken very seriously. Sir, the Common Minimum Programme really speaks about water management, and there is a particular reference to the linking of rivers. If not all rivers, at least, to begin with, they can think, how efforts can be made to link the Southern rivers. There is a talk and there can be a consensus also. The Government can initiate some consultation process; at Chief Ministers' level, a consensus can be created.

Having said this, I must say, there are other problems. Government now talks about 'inclusive growth'. There is really an economic exclusion ...*(Time-bell)*... of several sections, particularly, the weak and vulnerable sections, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. These sections stands very much neglected. If you go by actual figures of Budget, the actual money spent on their development is very meagre and it is not adequate. In fact, in the planning process, they are marginalised. There is an outcry, very strong outcry, among these people. There must be sub-plan, component plan for the SC/ST in the entire scheme of things by the Government.

Sir, there is a growing divide between the rural side and the urban side. This urban-rural divide is becoming more and more glaring and there is a big gap in the income levels of the people. Sir, we all swear in the name of Constitution. The Constitution talks about justice — social, economic and political. What about the economic justice? Even the spirit of the Directive Principles of our Constitution is that wealth shall not be concentrated in the hands of a few. But, in India, particularly after 1990s, the so-called reforms were introduced in our country. ...*(Time-bell)*... A few people are grabbing the wealth of the nation. They are becoming rich and super-rich. ...*(Time-bell)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please conclude.

SHRI D. RAJA: We cannot be proud of claiming that we have trillionaires or billionaires. We have poor people. Sir, the vast majority of our people are poor and vast majority of our people still struggle for drinking water, housing and passage roads to their villages. How is this Government going to address it? It is not that we are opposing the Bills. In any case, we will have to support these Bills. But the Government must have some serious introspection. The Government will have to go for mid-course corrections. The Left is supporting this Government. But it is not that we enjoy power without any responsibility. Without being in power, we feel more responsible, more answerable to the people. We are concerned with their problems. That is why we are telling the Government that it will have to make serious introspection; review your performance.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now conclude please. Please. Conclude now.

SHRI D. RAJA: Otherwise, there is no point in claiming that the UPA Government is an *'aam aadmi'* Government. This is what I would like to emphasise at this point of time.

SHRI RAMDAS AGARWAL: Sir, just one second only.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No; there is no time.

SHRI RAMDAS AGARWAL: Sir, I will not take more than a minute. He has referred to my speech. I just want to bring to the kind notice of Mr. Raja that during the NDA time, we distributed millions of tonnes of foodgrains to the drought-affected areas, to the flood-affected areas and to the poor. So, he should not blame us that today only we are taking of the poor.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): All right. Shri Sanjay Raut. ...(*Interruptions*)... No; no; please ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: When you came out with 'India Shining' campaign, the farmers were committing suicides under your regime. That is a fact. That is part of the history. ...(*Interruptions*)... That is what I am saying ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay; Shri Sanjay Raut. ...(*Interruptions*)... No; please Mr. Raja, that's okay. ...(*Interruptions*)... You have made your point. ...(*Interruptions*)... You have made your point; he has also made his point. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAMDAS AGARWAL: 'India Shining Programme' is not your subject. Your subject is, ...(*Interruptions*)... foodgrains to the poor. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, I am saying that the Government must strengthen the Public Distribution System and ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That's okay; you made your point and he made his point. ...(*Interruptions*)... That's all. ...(*Interruptions*)... Mr. Sanjay Raut. ...(*Interruptions*)... It is not an interaction session.

SHRI SANJAY RAUT (Maharashtra): Thank you, Mr. Deputy Chairman Sir, for the opportunity given to me to speak on this Appropriation Bill.

Sir, many hon. Members have already spoken on this subject. Shri Ramdas Agarwal has made very valid points in his speech. I would like to draw the kind attention of the hon. Finance Minister to two or three issues.

Sir, as the earlier speakers had mentioned, the rate of growth of GDP is about 10 per cent. But in the agriculture sector we are not getting the desired results. The poor people and farmers of this country do not know what economic growth and what growth in GDP is; they only want *roti, kapda aur makan.* Unfortunately, they are not getting these things.

All of us talk about ten per cent growth rate. It becomes a statistical thought. Sir, 0.2 per cent of our people are growing at a growth rate of 9.92 per cent per annum. But there is a very large proportion of our people whose growth rate is much below 0.2 per cent. More than 20 crores of our people live on below Rs. 15 per day. What is there to speak of our country's development now? Farmers in our country are living in poor conditions; their lives are worsening. According to one report in our country, one farmer commits suicide every thirty minutes. In my State, Maharashtra, especially in Vidarbha, more than 10,000 farmers have committed suicide in the last three years. It would really be a matter of shame for us if we have not get serious about and have not paid special attention to agriculture even sixty years after Independence.

Sir, the poor farmers are unable to repay their agricultural loans in any manner; they are unable to keep up their pride. Day-by-day, the number of farmers committing suicide is increasing. This trend has to be immediately arrested, failing which the results would be very serious. Loans are being advanced only to those eligible persons who have the capacity to repay them and not to others. This is the general rule. Everyone is well aware that agriculture is not a profitable job. People are born in debt and live in debt but those who also die in debts are only the farmers. This is the situation of our farmers. As far as I know, in Tamil Nadu, the Chief Minister, Shri Karunanidhi, has written off all the outstanding cooperative loans of farmers including interests on them. If Shri Karunanidhi can take this step in the interest of the farmign commuity, why can't a State like Maharashtra do the same? The nation cannot survive without the farming community. Save farmers, save India.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI SANJAY RAUT: Otherwise, we won't be able to talk of *Jai Jawan Jai Kisan.* Taking the cue from Shri Karunanidhi, all cooperative loans and loans from nationalised banks taken by farmers throughout India should be written off. Our country is about to become an economic super power, and yet, we cannot prevent our farmers from committing suicide. They are unable to repay debts even as little as Rs. 5000 or Rs. 10000. We claim ourselves to be a super power with a stupendous growth in the services sector, but we cannot provide economic security to two-thirds of our population.

Therefore, once again, I urge upon the Government to revise the package to cater to the needs of the farmers and also to waive off bank loans taken by them for agricultural purposes.

With these words, I conclude.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman Sir, I was taken aback this morning when I read a report that the Finance Minister has told the people that this year the rate of growth of GDP would be confined to nine per cent and that they should remain content with that.

SHRI P. CHIDAMBARAM: The last part is your addition!

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: All right, you did not ask the people to remain content with it but you have said that it would be limited to nine per cent!

SHRI P. CHIDAMBARAM: We have said that it is likely to remain at nine per cent.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Till yesterday, we were talking of a growth rate of ten per cent and the rate of growth of agriculture was 1.8 per cent. In the meanwhile, the Planning Commission has come out with figures that the rate of growth of agricultural products has increased to 4 per cent. It is very difficult to understand how the rate of general GDP comes down when the rate of growth of agriculture goes up. I have not understood the link between the two.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Of course, you understood, but you don't want to say.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: On the basis of the 4 per cent rate of growth of agriculture, I am of the opinion that if only certain policies are followed, then the rate of growth of general GDP can be as high as 15 per cent, and I would like to suggest to the Finance Minister some of the things, if done, I think, some of the Supplementary Demands could have been cut down. First, Sir, there is a demand now that the sugar factories should be given interest-free loan in order to ensure that their losses are wiped out or they are able to pay the cane prices. Sir, I have made a study on that and I can say that on the basis of what products the factories can make out for one tonne of sugarcane and what income they can get out of that, every type of factory can pay, for example, the Statutory Minimum Price. For a factory which has 10 per cent sugar recovery, SMP is only Rs. 728, while they actually get the income of Rs. 1,519. At the other extreme, the factory which has the recovery of 13 per cent, it gets Rs. 2032 as income and they are required to pay only Rs. 1007. What I am trying to say is: This claim that the sugar factories are making losses is entirely dishonest. What the factories in the North are doing is: They are not paying the farmers and developing a backlog, while the factories in the South are clamouring that even the Statutory Minimum Prices cannot be paid. I would like to ask, as a farmer, Sir, that this is a dishoest claim and if, at all, you want to give some money for the sugar sector, you should ensure that money goes directly to the cane growers rather than through the pipeline of factories through which the money doesn't appear to reach the farmers at all. Secondly, Sir, a major case of loss was about the wheat imports. Sir, there are some very serious mistakes and I am going to make an argument which possibly you can appreciate. Sir, on the 28th of February, you put a ban on taking open position on the futures market. On the 16th March, the Minister for Agriculture said—because the Indian futures were closed, he referred to the Chicago Board of Trade—that the current price was Rs. 744 and, therefore, the price of Rs. 850 as a procurement price was declared for wheat in India. Sir, that was the quotation for the month of March, while the procurement was to take place in the months of April and May. If he had only correctly referred to the contract prices of the Chicago Board for April and May, then he would have found that prices quoted even at that time were Rs. 1050 to Rs. 1100. If the correct price had been fixed as procurement price, then you would have got sufficient procurement and you would not have found yourself short of any wheat supply at all. Sir, further, when the first tenders were called, the tender that could be accepted was 263 dollars. At the time, rather than looking at the Chicago Board quotation, the Ministry of Agriculture preferred to look into some documents of a body of UNDP which claimed that the prices are going to come down, and on that basis they rejected that tender. In fact, if they had depended on the Chicago Board of Trade's calculation, they would have found out that the prices are actually going to go up. Second time when they accepted the tender of 325 dollars, they again made a wrong judgement, and I am making a very serious allegation that the Ministry of Agriculture deliberately chose to base themselves on documents which were convenient to the decision

they had already arrived at. And if this is what happened that cost us about Rs. 3000 crores, the policy on sugar is costing us Rs. 3000 crores. Sir, I would like ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Just two minutes, Sir. Senguptaji, the FIIs should be taxed. What I am trying to say is that the entire FIIs are coming only for industries and it is impossible to divert it to agriculture, and this can be done if we allow the forward trading and the futures market in agriculture and allow the financial investment and direct investment also in agriculture through the futures market. If that happens, I am quite sure that 15 per cent rate of growth is easily obtainable.

Last point is about retail trade. There are a number of people who stand for the small traders and defend the small trader as against the malls and the super markets. I can say that the farmer stand for the super market because the small trader has taken care of only his shop and he has not done anything to build up a chain between the harvest and the kitchen. What the malls do is to build up that chain, and therefore, farmers would like to have more malls that would build up the chain between the harvest and the kitchen. Therefore, do not think that there is opposition to the retail trade. It comes from a consumer category of urban people. The farmer is behind it and we expect the Government to provide police protection where the *goons* try to attack these malls.

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Thank you for giving me a chance to speak on this subject. While supporting these two Appropriation Bills, I would like to highlight some of the aspects of the economic policy of the Government. It is a pity that while the Government's economic policy is encouraging exclusive growth, they have now started taking about inclusive growth. Unless the basic characteristic of this economic policy of the present Government, which is continuously increasing disparity between the rich and the poor, is changed, they cannot dream of achieving inclusive growth about which they are now talking so highly. It appears that poverty and unemployment are going up due to poor public investment in agriculture and jobless growth of industry. Unemployment and poverty are mainly growing due to these two factors. Sir, after studying the whole aspects of economic policy, it appears that the overall anti-poor policy and withdrawal of subsidy from public utility services and foodgrain items of PDS, which appear to be basic features of the economic reforms policy of the UPA Government, are causing immense sufferings for the poor and the working-class people. So, whatever publicity the Government may make for the cause of the *aam aadmi,* but until and unless the economic policy is changed, no benefit can be accrued to this *aam aadmi.* I would like to emphasise one point that the latest three attacks on the poor farmers, small traders and common people are coming through three factors. First, through SEZs; secondly, through entry of corporate houses in retain trade; and, thirdly, through entry of corporate houses and FDI in agricultural marketing and contract farming. These three attacks, which are encouraged basically by the Government's economic policy, are causing increasing sufferings for the poor people and *aam aadmi.* Basically, until and unless these policies are changed, it will be useless to talk about inclusive growth of the society. I would like to say that continuing rise in prices of essential commodities and suicides by thousands of farmers should definitely be considered as dark spots on economic performance of the Government. This cannot be wiped out just by high-sounding publicity of GDP growth and Sensex rise. Sir, the Government's statistics can speak well about it. They can bear testimony to the continuous rising profitability of big corporate houses, and, on the other

hand, growing poverty and unemployment in the country. These cannot be any remedy on this aspect until and unless the present economic policy of the Government is changed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

DR. BARUN MUKHERJEE: So, we hope that the Government will think over it. They are now giving publicity to the inclusive growth but until and unless the basic aspects of the economic policy are changed, the inclusive growth in the society cannot be achieved. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you. Good point. Now, Shri Shunmugasundaram.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of the DMK Party, I support these two Appropriation Bills. Sir, the general feeling which has been expressed in this august House is that enough attention or priority is not given to the agriculture sector and agri-based industries. Sir, it is the duty of the UPA Government to alleviate this particular doubt. Sir, the promise made by the hon. Prime Minister that there would be four per cent growth in the agriculture sector has to be fulfilled, and, I request the hon. Finance Minister to respond to what has been done to give necessary support to the agriculture sector.

Sir, the Minimum Support Price of agriculture has to be increased in all the areas and it should be taken care of by the hon. Minister in the near future. The boom in the Sensex and the IT industries or IT-related services is encouraging but, in reality, what is happening is that these industries, particularly, the service industries, which are enjoying tax benefits from the Government, are investing in real estate in the country.

In this process, the real-estate price has gone up and this is the most unproductive growth in this country. A request the hon. Minister to put a check on this. I have also seen some of the non-agriculture, non-farming sectors like the educational institutions accumulating 400 or 500 acres of land. For what purpose they are doing so? They must be taxed. I congratulate the hon. Member Mr. Raut from Shiv Sena who recorded that the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar, had given relief to the farmers from the agriculture loan to the extent of Rs. 7,000 crores. That is a way to encourage the agriculture sector in the States. I also expect the hon. Finance Minister to extend similar benefits at the national level. Sir, the hon. Member Mr. Perumal ...(*Interruptions*)...

SHRI P. CHIDAMBARAM: You must appeal to all the Chief Ministers of the States.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: That is for the Finance Minister to write to all the Chief Ministers. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) You can also appeal to the Chief Ministers. No problem.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, hon. Member, Shri C. Perumal expressed his concern about the Cooperative Drinking Water Scheme, Hogenakkal. Sir, as far as my information goes—I believe the hon. Finance Minister will also clarify and inform this House—the State Government has written to the Central Government and the project has been taken up at the Japan bank level.

Sir, hon. Member Shri Sharad Joshi said about future contracts. Sir, as far as future contracts and future markets in agriculture are concerned—as far as my information goes and as far as what I have read—it is very good in many of the countries, and, particularly, with regard to

2.00 P.M.

the agriculture produce, the farmers are assured of their prices and the payments are made in advance, which must be given encouragement by the UPA Government. With these words, Sir, I support the Bills.

SHRI RAHUL BAJAJ: Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I stand here to support both the Appropriation Bills No. 4 and No. 5. Sir, I would like to put on record that I support these Bills as an independent member of this august House who was brought in this House by...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Independent 'honourable' Member.

SHRI RAHUL BAJAJ: Sir, I can't say that about myself. But, elected by all the four major parties, BJP, NCP Shiv Sena and Congress in Maharashtra. I may clarify for the few who don't know ..

SHRI P. CHIDAMBARAM: Now, he has said who sent him to the House.

SHRI RAHUL BAJAJ: The Finance Minister has a point of view, Sir. But three parties voted for me, and the 4th party, the Congress, also helped me come here because they put up a sacrificial candidate against me. And, therefore, as I say, I have come here with the unanimous support of all the four major parties.

Sir, I have to make three points while supporting both the Bills. I don't need to get elected by the *aam aadmi*. So, I don't talk of *aam aadmi* just as vote bank politics. But, I am talking of *aam aadmi*. This country can't move forward. We can't have a growth rate, whether 4 per cent in agriculture or total growth rate of 10 per cent or 15 per cent, which my friend, Sharad Joshi, is talking about, unless we have growth. So, we need growth, Sir. What does an *aam aadmi* need ultimately? Employment and rising income—whether in agriculture or anywhere else—and a control on inflation, not wholesale only, as my friend Arjun Kumar Sengupta said, but the prices that he has to pay can't be 7 per cent. That also has to come down to 3 per cent or 4 per cent. How do we do this? Or, what are the problems? There are many, but in the limited time that I will have, I would like to say that expenditures have to be controlled. Very rightly it has been said that governance is a major issue. Delivery and implementation are major problems. We all know it; the Finance Minister knows it; the Prime Minister knows it. But, we are not finding a solution. There is inefficiency; there is corruption. Please go in for public private partnership. Where private sector comes in, keep it accountable. Whether NGOs or corporate sector, keep them accountable because this is Government's money. But, take their efficiency into account. Do not any longer consider the private sector as somebody outside. We are domestic national private sector. Take our help wherever appropriate. So, public private partnership is very important.

Secondly, it has been mentioned by some hon. Members, subsidies have to be there. You can't remove them completely. But, why to the rich? Why to the people who are above the poverty line? Why non-merit subsidies? Where is the politics in that? Why to give subsidy on petrol? I say that as a vehicle manufacturer. Petrol is not used by the poor people. Oil Bonds are to partly help the oil companies. I believe bonds are not shown as deficit financing. I am subject to correction by the Finance Minister. If that is so, the deficit financing, that he assured us will remain under Budgetary figure for the current fiscal year, in spite of all other expenditure, is perhaps not the full deficit of this country, Sir.

My last point is the point, which was referred to by Mr. Arjun Kumar Sengupta, regarding exchange rate of the rupee. ultimately, 20 years down the line, if India has to be strong, I would like the rupee exchange rate as one dollar one rupee, not forty. You cannot be a strong country with a weak currency. But, gradually, in the right way, for fundamental reasons of the economy, not by FII money coming in. Let the FDI come in. What is this hot money coming in, whether for this sector or that sector. Yes, you did something for Participatory Notes. There was no openness there. (*Time-bell*) There was no transparency. Transparency was brought in. For years we have been saying about the Mauritius Agreement, even when Mr. Yashwant Sinha was there, in the NDA Government. Why don't we revisit it? is it because Mauritius is an Indian origin People friendly country? A lot of *ghotalas* are going on under that. A lot of wrong kind of money is coming in. Why can't we put some control on FII money? Because, what is happening with the exchange rate of rupee? Exports are suffering. Especially, the smaller companies, textile industry, auto components industry and many other industries are suffering. I export 20 per cent of my production. My margins are getting very much hit. Why are you hurting our exports? And more important, that has not been talked about, which is hurting Indian industries, small, medium and large, is imports from China. Shri Arjun Kumar Sengupta said that it was coming 'but.' What 'but?' That is not a market economy, I am sorry to say. The cost structure is opaque. They are not fully WTO-compliant. Put some anti-dumping duty on that. Don't let Chinese products come in till there is level-playing field for India. Don't even think of an FTA with China. That would be anti-nation, anti-India.

Through you, Sir, I would request the Finance Minister, who has done a great job during the last three years, to continue to help India, Indian people, Indian economy, and Indian industries. Indian industries, I repeat, are not foreign industries. Whether it is Bajaj or any other company, they are not foreign companies. We are as patriotic as anyone on the Left or the Right. Please support the farmer, the industrialist and the Indian people. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI RAHUL BAJAJ: Thank you, Sir.

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांग पर सदन में बहस चल रही है। जब भी इस तरह की मांग आती है, तो एक बात पर ध्यान जाता है कि योजनाकारों ने क्या व्यय का आकलन ठीक से किया था कि अनुपूरक मांग इस रूप में लाई गई। लेकिन यह तो परम्परा है कि अनुपूरक मांग हर साल पेश की जाती हैं महोदय, जो समाचारपत्रों में आया है, उससे इस देश में दो-तीन तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। एक वित्तीय प्रबंधन है, जिसको हमारे वित्त मंत्री जी ने कुछ क्षेत्रों में जिस ढंग से किया है, इसकी चर्चा भी निश्चित रुप से होती रहती है। एक दूसरी भी चर्चा होती है कि इस देश में कुछ ऐसे भी अरबपति हो गए हैं, जो दुनिया के अरबपतियों की अग्रणीय पंक्ति में चले गए हैं। इस देश में एक चर्चा यह भी चलती है कि आत्महत्याओं का दौर भी चल रहा है। हम वित्तीय प्रबंध को इस रूप में देखना चाहेंगे कि आम आदमी और जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उनकी क्रयशक्ति और उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है? इस आधार पर, यदि आज की अनुपूरक मांगों पर विचार किया जाए तो 75 प्रतिशत ऐसे लोगों की आबादी इस देश में है, जो या तो छोटे घरों में रहते हैं या झोंपड़ियों में रहते हैं। उनको जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं है और 33 प्रतिशत ऐसे लोग रहते हैं जो निरक्षर हैं। क्या भारत के वित्त मंत्री यदि ग्रोथ रेट के ऊपर संतोष कर सकते हैं, व्यापार संतुलन के मामले में संतोष प्रकट कर सकते हैं, मुद्रा भंडार के रूप में संतोष व्यक्त कर सकते हैं, यदि टैक्स स्ट्रक्चर सुधारने में विचार कर सकते हैं तो इस देश में आरक्षण समाज के कुछ वर्गों को दिया गया है और आरक्षण जायज भी है। क्या वित्त मंत्री इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि जो अविकसित हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, जिनके लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा है उनके लिए इस वित्त विभाग में कौन सा आरक्षण देने के लिए योजना बनाई है? हमें लगता है कि इस तरफ भारत की वित्तीय व्यवस्था निश्चित रुप से फेल हो गई है। यह आश्चर्य की बात है कि कृषि पर आधारित देश और गांवों में 75 प्रतिशत से अधिक

आबादी रहने वाले देश में गेहूं के आयात पर चर्चा होती है। गांवों के खेतों में इतना गेहूं पैदा नहीं हो रहा है। बाहर से गेहूं का आयात हो रहा है। महोदय, जब हम विद्यार्थी थे, उस समय भी हम एक बात पढ़ते थे कि अर्थशास्त्रीय मापदंड के कुछ बिन्दू हैं और माना जाता है कि उत्पादन और वितरण से इसका बहुत लिंक किया जाता है। उत्पादन के संबंध में भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं और वितरण के मामले में तो हमारा सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था निश्चित रुप से फेल हो गई है। मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि चार-पांच बातों के ऊपर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। इन्होंने भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के लिए अनुपूरक मांग मांगी। इन्होंने सरकार के लिए भी मांगा है। जो सरकारी विभाग यदि फायदे में चल रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा देने की जरूरत पर विचार करने का काम करेंगे। इसके साथ-साथ कृषि के कुछ क्षेत्रों में और गांवों के कुछ सवालों पर निश्चित रुप से प्राथमिकता देनी चाहिए, गांवों के किसानों को पानी दे दीजिए। उत्पादन बढ़ा दें। गांव का किसानों का जो लोन सिस्टम है, यह लोन कुछ रिड्यूस हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार): मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों और मजदूों को जो लोन दिया जाता है, जो इंट्रस्ट लिया जाता है, उस इंट्रस्ट को कम किया जाए। सिंचाई की व्यवस्था की जाए। मैं दो-तीन बिंदुओं को रखकर अपनी बात समाप्त करुंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप और छोटे-छोटे उद्योग समूहों का जाल बिछाना होगा, तभी गांव का उद्धार किया जा सकता है। गांव में एक एकड़ में एक परिवार काफी आमदनी पैदा कर सकता है। फसलों के प्रोडक्शन के स्वरूप बदलने पर विचार करेंगे, इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Thank you, Vice-Chairman, Sir, I rise to speak on the two Bills discussed on the House. Regarding the subjects discussed here I would like to highlight that the problems of Assam and the North-Eastern States are not taken care of ...(*Interruptions*)...

श्री अमर सिंह: सर, हमें इसका हिंदी अनुवाद चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No interpretation. Please check. अनुवाद हुआ है। Let me check. हो रहा है, आ गया है।

श्री अमर सिंह: शुरू से बोलिए।

SHRI KUMAR DEEPAK DAS:* I doubt if the problem of the north-eastern States are really understood. First of all, I would like to submit, the people of the State I come from, Assam, have been losing property worth crores of rupees every year due to flood. Thousands of people are suffering. Schemes which are undertaken to benefit the farmers and their economic growth are not implemented properly in Assam. We are talking about industrial development, agricultural development and economic development. It is said that the GDP growth is now at 9.1%. But in the picture of national growth Assam does not feature.

If does not show the real picture of the entire nation. The real picture is submerged in Assam, in the north eastern States where thousands of farmers are dying. They are committing suicide. That is the real picture of India today. The picture of a developed nation is hidden under this condition. The farmers all over the country are suffering today; but I think it is important to pay special attention to Assam. Agriculture expert Sri Swaminathan the hon'ble MP present here he had visited Assam. But I am afraid the Government of India did not pay adequate attention to his report and did not consider its suggestions. The suffering of the people of Assam with regard to price rise is much more than in other parts of the country. I would like to read out a statement made by the then Finance Minister, in 1978, in the Assam Assembly to high light the financial positions of our State.

*The speech was originally delivered in Assamese.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

Sir, I want to quote: "I rise to inform the hon. Members about a matter of public importance. As the hon. Members are aware, the Seventh Finance Commission have submitted their recommendations and these have been accepted by the Government of India with some modifications. Although as a result of the recommendations of the Finance Commission the total transfer of resources to the States would be more than doubled, the share of Assam in the transfer of resources in absolute terms has been far below our expectation with the result that instead of a revenue surplus which we were hoping for will be left with a substantial gap on the Revenue Account. During the Sixth Commission, the resource transfer actually received by us will amount to Rs. 489.34 crores whereas the total transfer likely to be received by Assam during the 5 years from 1979-80 to 1983-84, as a result of the Seventh Finance Commission's recommendations, will be only Rs. 518.65 crores. We are deeply disturbed to find that Assam's share of the total transfer of resources to all the States taken together has been reduced from 4.57 per cent during the period covered by the Sixth Finance Commission Award, to a mere 2.49 per cent for the next 5 years, covered by the Seventh Finance Commission. As a result, the doubling of the transfer of resources from the Centre to the States has hardly benefited our State." This was the statement made by the Finance Minister of Assam in the year 1978.

Same situation is prevailing in the State today. People are facing the same problems. That is why I say, it is necessary to pay special attention to Assam. The resources in Assam have to be streamlined. Assam has got special subsidies for economic and industrial growth. But have you noticed how much industrial growth has taken place? The Union Government should take note of this. A welknown politician from Assam had served the country as President of India. I am talking about Late Fakhruddin Ali Ahmed. When he was the President then he laid a foundation stone for a Jute Industry in his constituency Barpeta. That was my Assembly constituency also. but I am sorry to say, although the nation occasionally pays homage to him nothing is being done to fulfil his dream by starting the project. The foundation stone is now covered under a heap. Sir, we want to draw the attention of the Central Government to solve the problems faced by the people of Assam. Whatever developmental project has been taken up in Assam is progressing very very slowly. I want to mention the Begeebil Bridge project in this regard. The project which was to complete in 7 years, is taking 15 years. The Central Government had announced the project in 1997 to construct a bridge on the Brahmaputra. But it is going on a snails pace and is anticipated to be completed in 2012. Nothing can be more unfortunate. Sir, the people of Assam are suffering and facing problems in railways also. The problems of Assam should be considered national problem. The problem of floods in Assam should be considered as a national problem.

Vice Chairman, Sir, I want to say a few words about the problems face by the jute farmers. The price of jute has gone down. The farmers are not getting adequate price for their produce. They are suffering due to the loss.

I submit that the Central Government take note of the problems of the jute farmers of Assam and see that they get proper value for their products. If the farmers of Assam progress, the country progresses. I request the Hon'ble Minister to take not of this. With this I conclude my speech supporting the Bills. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sir, Tapan Kumar Sen. Please take two minutes.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I will complete within two minutes. I have got just

three questions. Thank you very much for giving me this opportunity. We had already discussed the economic disparities in the House the day-before yesterday. It was admitted that there were disparities and they had to be addressed.

Now, the first point is that the rate of growth of disparity is higher than the rate of the economic growth itself thereby reflecting a distributive distortion. I don't think that governance failure is the only reason. There is something wrong in the system and policy model. That is also affecting the governance changing its direction. So, it should be addressed.

Secondly, despite the buoyancy in the tax revenue, the accumulation of tax arrears is increasing, meaning thereby that the full potential of the economic growth could not be harnessed in revenue generation. I think, this area should be addressed very aggressively.

The third and the last point is that the flow of money in the form of FDI and FII is welcome, but not in an unregulated manner. Already certain alarm bell was rung by the Reserve Bank that some regulation was required to be there and it came out very specifically on banning the Paricipatory Note transactions. I think, the hon. Minister will enlighten the House as to what aggressive action is going to be taken in these areas. Thank you.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to the 19 hon. Members, beginning with Shri Ramdas Agarwal and closing the Comrade Tapan Kumar Sen, who participated in this brief debate on the Supplementary Demands for Grants. Sir, it is only right that the opportunity should have been availed of by the hon. Members to discuss the general economic situation, as well as, the economic policies followed by the Government. There have been some words of praise; there have been many points of criticism. I take both of them in the same spirit. While we welcome criticism, I wish to emphasise that an open economy and an open polity is the best road to economic prosperity. To envisage that we must have an open economy, it does not mean that economic activity will not be regulated. There will be regulation; but an open economy is very different from a closed economy or a controlled economy. Only the day-before-yesterday, the Prime Minister quoted the speech made by the Prime Minister of China. The Prime Minister is reported to have said, "Whenever China opened out to the world and opened its economy, China moved forward. Whenever we closed our economy and closed ourselves from the rest of the world China suffered". The Prime Minister's speech is reported extensively today in one of the newspapers, The Indian Express. I request the hon. Members, please read that.

Sir, I take the point that regulation and independent regulators are necessary for certain sectors of the economy. I belive that increasing openness of India's economy, pursuant to the reforms initiated in 1991, has been the single most important reason that we have moved from an average growth rate of less than five per cent to a situation where we can claim that we have moved to a higher growth rate of about nine per cent. In fact, there is discontent with nine per cent today. Please remember that for many years we were content with three-and-a-half per cent and five per cent. I welcome this discontent. We must always be dissatisfied with the growth rate that we have achieved and aim for more. I only wish that Shri Sharad Anantrao Joshi's prediction, not for the reasons that he has said, that we should move to a double digit growth, comes true. In fact, that is the goal of the Eleventh Plan. We will begin with a growth rate of about 9 per cent and by the end of the Plan, we hope to move to a growth rate of 10 per cent. While criticism of policies and the way it is implemented is welcome, I am, sometimes, disappointed when people criticise growth itself or people criticise parameters that measure growth. If we fail in delivering drinking water, if we fail in delivering

roads to rural India, if we fail in delivering medicines to rural people, the fault is not the fault of growth. What has growth got to do with failure of governance? It is growth which has given us the revenues which we can now apply to different sectors of the economy. Let me just compare two numbers. Just look at these two numbers. The kind of money that is now being applied to different sectors; the kind of money that is being made available to the States. These are facts. This is not meant to make any political point. In 2003-04, State's share of taxes was Rs. 65,784 crores. This year, it will be Rs. 1,42,450 crores. In 2003-04, grants and loans to State Governments was Rs. 71,583 crores. This year, it will be Rs. 1,06,987 crores. How did this happen? This happened because India's economy is growing at a higher rate, generating larger incomes for more people resulting in more tax and non-tax revenues to the Central Government, which we can share with the States. My only appeal to all sections of the people is, say what you want about the manner in which we apply resources, say what you like about the manner in which we govern the country, but do not run down growth. Shri Rahul Bajaj made the point quite effectively. Growth is imperative. Inclusive growth is the goal and we must work hard to make this growth inclusive growth. Faster and inclusive growth is the title of the Eleventh Plan Document and I must respectfully urge all sections of the House to please support the policies that promote faster growth, but hold us accountable if we cannot deliver inclusive growth. Naturally, concern was expressed about agriculture. I would, therefore, take just a few minutes to explain what we are doing in agriculture. In the current year, agriculture growth rate is, at least, 70 basis points higher than the last year's. I am, therefore, confident that the year will end with a higher growth rate of agriculture, perhaps 3.6 per cent, closer to 4 per cent. But I cannot say whether we will touch 4 per cent. We might be close to 3.6 per cent. Our aim is to raise agriculture growth to 4 per cent. Without agricultrue growing at 4 per cent, it is not possible to address the fundamental issues of rural poverty and rural incomes. The other two sectors are growing at close to 9 per cent. But if agriculture continues to grow at rates of 2 and 3 per cent, the disparity will only become wider. In fact, even if agricultrue grows at 4 per cent, there will be disparity. But we must ensure that agriculture grows, at least, by 4 per cent a year.

A number of initiatives have been taken by this Government. Recently, we announced the Rashtriya Krishi Vikas Yojana. An additional Rs. 25,000 crores, over and above the budget presented in February 2007, have been provided, over a period of time and the Food Security Mission has been launched. We have drawn heavily from all the reports that have been made available on the agriculture sector. Sir, specific initiatives include, in technology, research priorities will shift towards evolving a cropping system to suit agro climatic conditions. The ICAR would be restructured for evolving appropriate cropping systems. In irrigation, as the scope for new, large surface projects is limited, the focus would be to complete the ongoing projects by increasing allocation under AIBP. More emphasis will be placed on participatory irrigation management. In ground water exploitation, priorities would be areas of abundant availability such as Assam, Bihar, Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand, parts of Uttar Pradesh and West Bengal. The National Rainfed Area Authority will focus on the problems and potentials of rainfed areas. Input and support services would be strengthened. Efforts will be made to have more inclusiveness in the credit access even while we acknowldge that the total volume of credit has expanded. The new food security mission will attempt to reduce the yield gaps within States and between States, and aim at increasing the foodgrains production by, at least, 20 million tonnes — 10 million tonnes of paddy, 8 million tonnes of wheat and 2 million tonnes of pulses. Appropriate emphasis will be placed on diversification of agriculture. And equity issues for small farmers' needs would be given special consideration.

As far as irrigation is concerned, the total outlays in the Eleventh Plan, at constant prices, is tentatively put at Rs. 54,701 crores, as against the Tenth Plan outlay, at 2001-02 prices, of Rs. 20,513 crores. In addition, Rs. 25,000 crores as Central Assistance to States, through the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, will be provided. Further, for irrigation, the total outlay proposal is Rs. 1,82,050 crores under the State Plan; Rs. 45,415 crores for AIBP, and Rs. 4470 crores under Central Plan. Thus the total for irrigation will be Rs. 2,31,935 crores. As I said in the other House, the real issue is: Are these monies being well spent and will these monies be well spent? Today, I am sorry to say that most programmes under irrigation are contractor-based, not beneficiary-based. The happiest lot for all these allocations must be the contractors. Therefore, unless we improve the efficiency of implementing these projects, without leakage, without wastage, without corruption, whatever money is provided will not achieve the goals. Therefore, I appealed in the other House, and I appeal to this House; I know there is leakage in many programmes. But, at least, as far as irrigation is concerned, if we can spend this money efficiently, -- it is a huge amount of money; something like Rs. 2,31,935 crores in a period of five years — without leakage and without corruption, the entire landscape of agriculture in this country will be dramatically changed over the next five years.

Sir, as for the expenditure on Agriculture Research and Education, in 2003-04, the total amount was Rs. 1,435 crores. We have stepped it up year after year and, for the current year, it is Rs. 2,458 crores. This is still a small amount. I will try to provide more. But the fact is that we have raised it from Rs. 1,435 crores to Rs. 2,458 crores. We have added a huge extent to irrigated land. The total land, that has been added, is quite large. At the end of the Eighth Plan, the total land for assured irrigation was 86 million hectares; under the Ninth Plan, it was 94 million hectares; under the Tenth Plan, it was 103 million hectares. I have just given you the figures for the Eleventh Plan, and I am confident that if we reach the physical targets of the Eleventh Plan, not merely the financial outlays of the Eleventh Plan, if we achieve the physical target of the Eleventh Plan by spending this money, the landscape of agriculture will be dramatically changed over the next five years.

Sir, besides irrigation, the Bharat Nirman has a number of components, and each component of the Bharat Nirman is addressing a concern of rural India, drinking water, rural roads, rural housing, rural electrification and rural telephone connectivity. I don't wish to take the time of the House in listing the achievements of the last two years as well as the achievements of the current year, but, these are target-driven programmes where we have measurable targets and these targets are being measured and monitored, and I hope that as and when we achieve these targets, the people in rural India will find that the quality of their life has improved, at least, a little; that life is a little better to live with roads, with drinking water, with electricity and with telephones.

Sir, there was a lot of discussion about procurement prices. Needless to say, our Government has increased procurement prices. I have given these figures in the past. For a period of five years, the procurement price of wheat was increased by ten rupees a year, on an average by about 50 rupees. Today, the procurement price of wheat is 1,000 rupees for the next *Rabi* season. These are the numbers. In 1999-2000, the MSP for wheat was 580 rupees a quintal; by 2003-04, it had come to 630 rupees a quintal, 50 rupees in five years. For *Rabi* 2008, it is 1000 rupees a quintal. Like-wise, in 1999-2000, for paddy A-grade, it was 520 rupees a quintal; by 2003-04, it had come to 580 rupees a quintal, a rise of 60 rupees. We are now offering for the current year 775 rupees, which is a rise of 195 rupees in four years.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Why is there disparity with wheat when the growth is the same? ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Just one second. I will answer. I have noted your point. The MSP is fixed on the recommendation of the Committee on Agricultural Costs and Prices, CACP. In the case of wheat, after calculating the costs, — and this is considered an expert body — they had recommended 1000 rupees and we have accepted 1000 rupees. In the case of paddy, we have added a hundred rupees to the recommendation of the CACP as bonus. Therefore, we have not given less than what the Committee recommended. We have actually given more than what the Committee recommended. The demand is, you should give more, even more. That is the demand. Therefore, we go by an expert Committee. We have accepted their recommendation. In the case of wheat, we have given exactly as per the recommendation. In the case of paddy, we have given a hundred rupees more than the recommendation. Any demand for even more would, of course, have to be considered by the appropriate Ministry. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: The Expert Committee's figures can be questioned because the Field Investigators have not visited the villages; they have not gone to farmers. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is the same thing. You can ask it after this.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (Madhya Pradesh): Sir, since the hon. Minister is replying to this point. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't ask in the middle. ...*(Interruptions)*... It is not a good practice to intervene when the Minister is replying.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, since he is answering this point. ...*(Interruptions)*... I have just one sentence. Sir, in 1995, the wheat price and paddy price was the same. ...*(Interruptions)*... Over the years, the difference started with Rs. 50, Rs. 100. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: I understand that. ...*(Interruptions)*...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Now, the difference is Rs. 300. Why don't you increase it to Rs. 1000? ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Thirunavukkarasar, in 1995 also, the MSP was fixed based on the recommendation of the CACP. In 2007 also, the MSPs are fixed based on the recommendations of the CACP.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Then there is something wrong with the recommendation of the Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different question. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is a different matter, if you question the conclusions of the CACP. I mean, you were in the Government; your party was in the Government, at no time, do I recall the NDA questioning the recommendation of the CACP. Shri Chaturanan Misra was the Minister for Agriculture between 1996-98, I cannot recall his questioning the recommendation of the CACP. If something is fundamentally wrong today with the CACP, you can raise this issue, I am sure, the Minister will answer. But all I am saying is, while replying to a general debate. I am pointing out that we have gone by the recommendation of the CACP. But certainly that does not prevent any hon. Member or any expert from questioning

the recommendations of the CACP and raising a debate on that issue. I am sure, the Minister will answer that debate.

SHRI D. RAJA: There is a demand by the farmers. They want a thousand rupees per quintal of rice.

SHRI P. CHIDAMBARAM: That is a demand that you should make to the Minister concerned. I have answered why this price has been fixed in this manner. Sir, let me run through the points very quickly.

Sir, there was some question about the PDS. Sir, we are not reducing the subsidy for PDS. I know that some answer was read. Please remember, I can give you the details, the Budgeted provision was higher than the previous year. You are reading the RE figures. The RE figures came down because of a decentralised procurement system and because of lower interest rate in that year the carrying cost of food of FCI came down. You should not look at only the RE figures. Because of other variables like interest rate or carrying cost coming down, the subsidy bill will come down. The question is, was the quantity of foodgrains that was subsidised remains the same, or has it come down. In fact, we have not increased the price, at all, of foodgrains since this Government came. Therefore, the subsidy, in fact, is the same subsidy; in fact, the subsidy has increased; MSP has increased; we have not increased the issue price at all. Therefore, the subsidy actually has increased.

If FCI, because of its more efficient decentralised procurement and because of lower interest rate, is able to reduce the subsidy bill, that does not mean that subsidy per kilogram of foodgrain distributed to the poorest comes down. I am sure the hon. Member understands the point I am trying to make. Look at the BE and look at the RE.

Sir, I wish to point out that an evaluation has been made on the Public Distribution System. Dr. Arjun Sengupta said, we must have a targeted intervention. The PDS is a targeted intervention. In fact, the Left parties say that it should not be targeted and that it should be universal. The PDS, in fact is a targeted PDS today. Look at the conclusions of the report. The report concludes that on all India basis, 36.38 per cent of foodgrains do not reach the poor. 16.67 per cent is the leakage attributed to ghost ration cards, and 19.71 per cent is the leakage in the fair price shop. It varies from State to State. If I read the figures for some States, it is extremely alarming. It is a shameful record. I will not read the figures State by State.

For all India, 36.38 per cent of the foodgrain do not reach the poor! Therefore, the fault does not lie in the supply of foodgrain. The fault lies in the manner in which the food is distributed to the poor. This is why I say, while policies can be criticised — every party is entitled to hold its policy and propagate its policy; different Governments have been there, different policies are being followed. The fault that is attributed to the policy, I think, pales in comparison with the fault that should be attributed to the manner in which the policy is implemented.

I know, there are some policy failures. But the greater part of our failures is not in policy, but in its implementation. If we can only distribute the foodgrains.....

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Who is responsible?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I will answer who is responsible. The State Governments are solely responsible for distributing the foodgrains through the PDS. The Government of India can only give the foodgrains today. It is the State Governments that are entirely

responsible for distribution. They lift the stock, they give it to the fair price shop, they issue the ration card, they weed out ghost ration cards; it is entirely their responsibility.

My party is also in State Governments. I am not running away from the problem. If the Congress Party is in State Government and things are going wrong, then the Congress party is responsible. Equally, every party in the State Government is responsible. All I am trying to say is, we can certainly discuss policy failures, but whatever the policy is, unless the implementation is strong, how do we carry out policies in this country?

Sir, very quickly, let me run through a few points. Dr. Arjun Sengupta said, I am a little surprised, that these levels of growth rates have been achieved in the NDA period also. That is not correct at all. The first five years of NDA period, under one Finance Minister returned an average growth rate of 5.3 per cent. Let us get that number burnt into our memory - 5.3 per cent. In the last year — another Finance Minister - it went to 8.5 per cent. The average, therefore, for six years was 5.8 per cent. The average for the six years was 5.8 per cent; the average in our Government is 8.6 per cent. Therefore, I think, we should not make this mistake. Our memory should not be allowed to play tricks; — I am sure that any Government, the next Government and next Government should aim higher. We have aimed higher, we have achieved the higher growth rate, and I am sure every Government would want to aim higher than the previous Government. Sir, very quickly, I come to Service Tax. ...*(Interruptions)*... Again memory is playing tricks. Service Tax was introduced not by the UPA Government; it was introduced by Dr. Manmohan Singh in 1994-95.

SHRI RAMDAS AGARWAL: I did not raise any objection why this had been introduced. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am going to answer it. ...*(Interruptions)*... Now services sector occupies 54 per cent of India's GDP. Can that sector go without paying any Service Tax? If manufacturing can pay Excise Duty, which is a value added tax, the services sector must also pay Service Tax, which is a value added tax. ...*(Interruptions)*... Just a moment, please. ...*(Interruptions)*... So, the First Service Tax was introduced in 1994-95. Then I think, the United Front Government added 11 services; the NDA Government added 37 services and remaining have been added by the UPA Government. But this is inevitable. From the 1st of April of 2010, we are moving towards a GST. What is GST? It is Goods and Services Tax. Excise Duty and Service Tax will be combined into one tax called GST. Therefore, those of you who think that Service Tax is an abomination, I would respectfully request you to revise your view. Service Tax is not an abomination; Service Tax is a value added tax which falls upon services like Excise Duty falls upon goods and from 1st of April, 2010, we will have a combined tax which falls on both goods and services. The State Governments are on board, the State Finance Ministers are on board, the State Chief Ministers are on board and I think hon. members of Rajya Sabha should also come on board and accept that GST will come on the 1st of April, 2010. Sir, there was talk of revenue forgone. I wish I could make it zero. But then hon. MPs must stop writing me letters — give exemption to this sector, give exemption to that sector and make this Duty zero Duty. ...*(Interruptions)*... That is a different matter. But the point is revenue forgone is because some sectors deserve relief. For example, agriculture sector deserves relief. Therefore, agricultural hand tools come at zero Excise Duty. Should I put Excise Duty on agricultural hand tools? I cannot. I should not. Therefore, a number of sectors deserve relief, agriculture deserves relief, exporters deserve relief, and small-scale industry deserves relief. We have given Excise exemption of one-and-a-half crore to small-scale industry. Therefore, when sectors

deserve relief, we give the relief. But I agree with Rahul Bajaj that while we are giving relief to deserving sectors, we are also giving relief to undeserving sectors. While we are subsidising merit goods we are also subsidising non-merit goods, While we are subsidising the goods and services consumed by persons below the poverty line, we are also subsidising the very same goods and services consumed by persons above the poverty line, But, I think we need to take a look at subsidies. I am willing to come back for a full discussion on subsidies; it is nobody's case that all subsidies will go. No. Even the affluent countries subsidise. We must subsidise food in this country. We must subsidise fertilisers in this country, we must subsidise some fuels in this country. But we must revisit subsidies once in three years, once in five years, remove the non-merit subsidies, and focus subsidies only on deserving sectors and for deserving sections of the people.

-Sir, there was some question about education loan, I do not know why. I am not saying that every deserving student has got a loan. I know there are Branch Managers who are unhelpful. But the point is when we took over only 3,19,337 students had got education loans and the total amount outstanding was Rs. 4550 crores. Today, it is 9,54,729 students and the total amount given as educational loan is Rs. 14,810 crores. This is as of June, 2007. My unverified numbers say that the number of educational loans in the country has crossed 10 lakhs. It was 3,19,000. Today, it is 10 lakhs. And, I assure you, once again, it is my intention, that every deserving student, who has got the minimum mark, who has gained admission to one of the listed courses in an accredited institution should be given an edcuational loan and no Branch Manager should be allowed to deny a loan and every complaint must be investigated. I can honestly and proudly claim that every complaint has been investigated to its logical conclusion until I am personally satisfied, not my officer, that the loan has been either granted—they give eight out of every ten—or in two out of every ten cases they satisfy me that for the following reasons that student does not deserve a loan. It takes a considerable part of my time. But, I do not mind, I have committed to expending this programme and I will ensure that this programme grows from year to year.

Finally, there was some question about the diploma in nursing. I do not know whether the hon. Member is here. His information does not seem to be correct. Information I have got is, if the candidate has obtained a diploma from an institute recognized by the Central Nursing Council or the State Nursing Council, irrespective of whether it is a private sector college or the public sector college, such candidate is eligible for Government jobs.

I think, I have answered most of the points.

Sir, an hon. Member expressed his appreciation for my 'sincerity and commitment' and raised a concern that I was, perhaps, unwittingly not revealing information about the company. It is entirely incorrect. The company was investigated and a Show-Cause notice was issued.

The Show-Causes notice—kindly mark the dates—was adjudicated on 11th July, 2003 and a demand for Rs. 240 crores of Excise Duty and Rs. 9.26 crores of Customs Duty was confirmed. This was in the NDA Government. The party filed an appeal. In the meantime, our party came into office. Our Government, my Ministry my Department defended the appeal and the appeal was rejected by the Tribunal by an order dated 17th June, 2005. We did not lose the case; we won the case. A further appeal was filed in the High Court. My Government, my Department defended the appeal in the High Court. The High Court dismissed the appeal on 3rd May, 2006 confirming the demand. Therefore, in two appellate courts, we have won the case against the party. Now, the party has gone to the Supreme

Court. The next date of hearning is a date which will be fixed. So, we are defending the case and we will defend the case in the Supreme Court and I am confident that our lawyers will be able to sustain this demand.

SHRI AMAR SINGH: I am fully satisfied with the hon. Minister.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I will add further. Four of the officers of the company are being prosecuted and a complaint has been filed before the Magistrate on the 21st September, 2007. So, no favour is being shown to any one. There are industrialists in this House. There are people connected with industry. I have no friends, I have no enemies in industry, No industrialist in this country can claim that he is close to me or is a friend of mine or he has got a favour form me. I repeat that I have no friends and no enemies in industry. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up for consideration the Appropriation (No. 4) Bill, 2007. The question is:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2007-08, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motions were adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2,3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I move:

That the Bill be returned,

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall, now, put up the Appropriation (No. 5) Bill, 2007 to vote, The question is:

> "The Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2006, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2,3, and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.